mediaauditornews@gmail.com Epaperdainikmediaauditor.in वर्ष-06 अंक-140 पृष्ठ-8 मूल्य-3 रूपये

सतना

22 मई 2026 शुक्रवार

दैनिक

मीडियाऑडीटर

सतना, रीवा एवं मनेन्द्रगढ़ से एक साथ प्रकाशित

वायरल गर्ल बोली- ओरिजनल बर्थ सर्टिफिकेट बदला गया

इंदौर हाईकोर्ट में लगाई याचिका, खुद को बताया बालिग

इंदौर, एजेंसी। 'वायरल गर्ल' ने खुद को बालिग साबित करने के लिए बुधवार को अपने पति के साथ इंदौर हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। दावा किया है कि उनकी शादी को अपराध की श्रेणी में लाने के लिए सरकारी जन्म प्रमाण पत्र में फर्जी बदलाव किए गए। उन्हें नाबालिग दिखाने की कोशिश की गई।

याचिका में कहा गया है कि मूल जन्म प्रमाण पत्र को बिना नोटिस और कानूनी प्रक्रिया के सरकारी पोर्टल से हटा दिया गया। उसकी जगह कथित रूप से गलत जन्मतिथि दर्ज कर दी गई। साजिश कर नाबालिग दिखाया गया। मूल जन्म प्रमाण पत्र बहाल करने और सरकारी रिकॉर्ड में छेड़छाड़ की स्वतंत्र जांच की मांग की है।

फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी मुलाकात

याचिका के अनुसार, वायरल गर्ल की मुलाकात केरल में फिल्म शूटिंग के दौरान एक युवक से हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ीं और मार्च 2026 में दोनों ने शादी कर ली। खरगोन जिले की रहने वाली लड़की पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों के कारण चर्चा में आई थीं।

पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड हमज़ा बुरहान मुजफ्फराबाद में मारा गया

नई दिल्ली, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड हमज़ा बुरहान पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) के मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों के हमले में मारा गया। उसे कई गोलियां लगीं। हमले के बाद उसके साथियों ने उसे तुरंत पास के अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

विदेशी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 27 साल का हमज़ा बुरहान भारत में प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र से जुड़ा था। उसका पूरा नाम अरजुमंद गुलजार डार था, जिसे उसके सर्किल में 'डॉक्टर' के नाम से भी जाना जाता था। पुलवामा के रत्नीपुरा इलाके के ग्राम खरबतपोरा में पैदा हुआ हमज़ा 2017 में उच्च शिक्षा के बहाने पाकिस्तान चला गया था। बाद में वह प्रतिबंधित आतंकी संगठन अल-बद्र में शामिल हो गया और आखिरकार कमांडर के रैंक तक पहुंच गया।वह कश्मीर घाटी में कई आतंकी हमलों में शामिल था। हमज़ा 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। उसे पीओके मुजफ्फराबाद में अज्ञात बंदूकधारियों ने मार गिराया। हमलावरों ने मुजफ्फराबाद स्थित एआईएमएस कॉलेज के बाहर उस पर ताबड़तोड़ फायरिं की जिसमें वह गिर पड़ा।

गौरतलब है कि हमजा की मदद से आतंकियों ने पुलवामा के लाथपोरा में श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे पर सीआरपीएफ के काफिले पर आत्मघाती हमला किया था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान बलिदान हो गए थे। इस घटना के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए थे, वहीं भारत ने पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकानों पर हमले किए थे।

नीट पेपर लीक केस में लातूर से डॉक्टर गिरफ्तार

बेटे के लिए गेस पेपर खरीदा था; मुख्य आरोपी 'एम सर' स्कूल और कॉलेज खोलने वाला था

लातूरे, एजेंसी। नीट पेपर लीक में CBI ने महाराष्ट्र के लातूर से एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि डॉ मनोज शिरुरे ने बेटे के लिए RCC कोचिंग के संचालक और आरोपी शिवराज मोटेगांवकर उर्फ 'एम सर' से गेस पेपर खरीदे थे।सीबीआई ने बुधवार को पुणे में पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया। जानकारी आज सामने आई है। इस मामले में किसी पेरेंट्स की यह पहली गिरफ्तारी है। नीट पेपर लीक में यह 11वीं गिरफ्तारी है।

इससे पहले महाराष्ट्र से 6, राजस्थान से 3 और हरियाणा से एक व्यक्ति को अरेस्ट किया। इनमें 2 महिलाएं भी हैं। उधर, इस मामले में लगातार नए खुलासे भी हो रहे हैं। CBI जांच में पता चला है कि शिवराज लातूर में 8 एकड़ जमीन पर स्कूल-कॉलेज खोलने की तैयारी में था।

आरजीकर केस-कलकत्ता हाईकोर्ट का सीबीआई को दोबारा जांच का आदेश

घटना वाले दिन क्या हुआ, फिर से छानबीन करें; किसी से भी पूछताछ की छूट

कोलकाता, एजेंसी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजीकर रेप मर्डर केस को दबाने के आरोपों की जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने CBI की 3 सदस्यीय SIT बनाने का आदेश दिया। जिसकी अगुवाई CBI के पूर्वी क्षेत्र के जॉइंट डायरेक्टर करेंगे। SIT को 25 जून तक रिपोर्ट देनी होगी।

हाईकोर्ट ने CBI को उस रात की पूरी घटनाक्रम की दोबारा जांच करने को कहा है। साथ ही कोर्ट ने CBI को जरूरत पड़ने पर किसी से भी पूछताछ करने की अनुमति दी है।

कोर्ट ने यह आदेश पीड़ित के माता पिता की तरफ से लगाई याचिका पर दिया। पिछले साल 17 मार्च को पैरेंट्स ने CBI पर केस की सही जांच नहीं करने और मामले को दबाने का आरोप लगाया था।

सुप्रीम कोर्ट ने पेरेंट्स को कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर करने की परमिशन दी थी।

आरजी कर हॉस्पिटल में 8-9 अगस्त 2024 की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप-मर्डर हुआ था। 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी। 20 जनवरी 2025 को सेशंस कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

पीड़ित की मां रत्ना देबनाथ भाजपा विधायक बनीं

आरजीकर रेप-मर्डर केस में पीड़ित की मां रत्ना देबनाथ अब विधायक बन चुकी हैं। वे पानीहाटी से भाजपा विधायक हैं। गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वह कोर्ट में मौजूद रहीं।

यूपी का बांदा दुनिया में तीसरा सबसे गर्म शहर

- **नौतपा से 4 दिन पहले ही 48डिग्री पहुंचा तापमान; म.प्र.-महाराष्ट्र में भी पारा 47 डिग्री**

भोपाल/जयपुर/लखनऊ/पटना, एजेंसी। 25 मई से नौतपा शुरू हो रहे हैं, लेकिन उससे पहले ही तापमान 48डिग्री पहुंच गया है। यह आंकड़ा उत्तर प्रदेश के बांदा में रिकॉर्ड हुआ। तापमान के लिहाज से 20 मई को बांदा दुनिया का तीसरा सबसे गर्म शहर रहा।

बांदा से ज्यादा तापमान केवल मिस्र के असवान में 49.4डिग्री और सऊदी अरब के अराफात में 48.4डिग्री रिकॉर्ड किया गया। दुनियाभर में सबसे ज्यादा तापमान की लिस्ट में खजुराहो 47.4डिग्री के साथ चौथे नंबर पर रहा।

बुधवार को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, ओडिशा और महाराष्ट्र के 16 शहरों में भी तापमान 46डिग्री से ज्यादा रहा।मौसम विभाग के मुताबिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान और थार मरुस्थल से आ रही सूखी और गर्म हवाएं सीधे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में पहुंच रही हैं।

माउंट एवरेस्ट पर नया रिकॉर्ड: एक दिन में 274 पर्वतारोहियों ने की चढ़ाई, तीन भारतीय भी शामिल

काठमांडू, एजेंसी। नेपाल में स्थित माउंट एवरेस्ट पर 274 पर्वतारोहियों ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की। इसमें तीन भारतीय भी शामिल हा। जिन्होंने एक दिन में सबसे अधिक चढ़ाई का नया रिकॉर्ड बनाया। सभी 274 पर्वतारोही बुधवार को 8,848.86 मीटर की चोटी पर पहुंच गए।

तीन भारतीय शामिल

नेपाल में अभियान संचालक संघ के महासचिव ऋषि राम भंडारी ने बताया कि 150 नेपाली शेरपाओं सहित ये पर्वतारोही एक ही दिन में शिखर पर पहुंच गए। विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली टीम में शामिल तीन भारतीय पर्वतारोही तुलसी रेड्डी पालपुनूरी, संदीप अरे और अजय पाल सिंह धालीवाल हैं।

पहले क्या रिकॉर्ड क्या था?

उन्होंने कहा कि यह इस वसंत ऋतु में एवरेस्ट शिखर पर पहुंचने वालों की ओर से बनाया गया नया रिकॉर्ड है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि 502 पर्वतारोहियों ने 2026 के वसंत में एवरेस्ट पर चढ़ाई करने की अनुमति प्राप्त कर ली है। इससे पहले, मई 2019 में, नेपाल की तरफ से एक ही दिन में 223 पर्वतारोही शिखर पर पहुंचे थे।

11 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी महिला

वहीं, गुरुवार को भारत के लक्ष्मीकांत मंडल ने भी विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ाई की। अभियान के आयोजक पायनियर एडवेंचर प्राइवेट लिमिटेड के अनुसार, मंडल ने छह नेपाली शेरपाओं सहित आठ अन्य लोगों के साथ एवरेस्ट पर चढ़ाई की। इस वसंत ऋतु में स्थापित किए गए अन्य नए रिकॉर्ड नेपाल के कामी रीता शेरपा द्वारा बनाए गए हैं, जिन्होंने 32वीं बार शिखर पर चढ़कर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसी तरह, नेपाल की ल्हाकपा शेरपा इस सीजन में रिकॉर्ड 11 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला बन गईं।

बीएचयू में 'ब्राह्मणवादी पितृसत्ता' प्रश्न पर विवाद

एबीवीपी छात्रों ने इतिहास विभाग के बाहर किया विरोध, कमेटी गठित पर जांच करने की उठाई मांग

वाराणसी, एजेंसी। बीएचयू में एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षा में पूछे गए एक प्रश्न को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। इस मुद्दे पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े छात्रों ने इतिहास विभाग के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने बैनर-पोस्टर लेकर जमकर नारेबाजी की और विश्वविद्यालय प्रशासन से पूरे मामले की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। पेपर को इतिहास विभाग के प्रोफेसर सुतापा दास ने तैयार किया था, हालांकि विवाद के बाद से उनके तरफ़ से कोई बयान नहीं जारी किया गया है। इतिहास विभाग के गेट पर प्रदर्शन बुधवार को इतिहास विभाग के बाहर बड़ी संख्या में छात्र एकत्र हुए। अभाविप बीएचयू इकाई के अध्यक्ष पल्लव सुमन ने कहा कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जैसी प्रतिष्ठित संस्था में विद्यार्थियों से वैचारिक रूप से प्रेरित प्रश्न पूछना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है।

शिमला एयर कनेक्टिविटी पर हिमाचल हाईकोर्ट सख्त

केंद्र सरकार को नोटिस जारी; सेवाएं जारी रखने के आदेश; 7 महीने बाद उड़ान शुरू

शिमला, एजेंसी। हिमाचल हाईकोर्ट ने शिमला की हवाई सेवाओं को लेकर केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में शिमला की एयर कनेक्टिविटी में कोई रुकावट न आए। कोर्ट ने इसे लेकर केंद्र सरकार से कहा कि अगली सुनवाई तक हलफनामा दाखिल करने के निर्देश दिए।चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बीसी नेगी की बैंच ने यह भी पूछा कि संशोधित उड़ान योजना कब लागू होगी और चंडीगढ़-शिमला रूट पर ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर सेवा कितनी संभव है। केंद्र सरकार ने कोर्ट को बताया कि शिमला एयरपोर्ट पहाड़ी इलाके में होने के कारण सीमित सुविधाओं वाला एयरपोर्ट है और यहां रनवे बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है।फिलहाल केवल दो ATR-42 और एक हिंदुस्तान-228 विमान ही ऑपरेट हो सकते हैं। इनमें से एक ATR विमान दिल्ली-शिमला रूट पर 11 मई 2026 से फिर शुरू किया गया है।

ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर पर हो रहा विचार

कोर्ट को यह भी बताया गया कि चंडीगढ़-शिमला हेलीकॉप्टर सेवा के लिए ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर पर विचार हो रहा है। फिलहाल पवन हंस की सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर सेवा चल रही है, जिसमें केवल 4 से 6 यात्री सफर कर सकते हैं और यह सप्ताह में सिर्फ तीन दिन चलती है। कोर्ट ने माना कि यह सेवा पर्याप्त नहीं है।

ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर में ज्यादा यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे

कोर्ट ने कहा कि ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर ज्यादा यात्रियों और सामान के साथ बेहतर सेवा दे सकता है। साथ ही राज्य सरकार से पूछा गया है कि क्या ऐसे हेलीकॉप्टर की लैंडिंग जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट के अलावा शिमला या संजौली के पास किसी अन्य जगह भी कराई जा सकती है, क्योंकि जुब्बड़हट्टी एयरपोर्ट शहर से करीब 35 किलोमीटर दूर है।

विजय की कैबिनेट का विस्तार 23 मंत्रियों ने शपथ ली

तमिलनाडु में कांग्रेस 59 साल बाद सरकार का हिस्सा बनी, दो विधायक बने मंत्री

चेन्नई, एजेंसी। तमिलनाडु में कांग्रेस 59 साल बाद सरकार का हिस्सा बन गई। कांग्रेस विधायक एस राजेश कुमार और पी विश्वनाथन आज विजय की कैबिनेट में शामिल हुए।

राजेश कुमार किलियूर और विश्वनाथन मेलूर सीट से विधायक हैं। शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार सुबह 10 बजे हुआ। इस दौरान TVK से 21 मंत्री और कांग्रेस से 2 मंत्रियों ने शपथ ली।

VCK और IUML को भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, विदुथलाई चिरुथइगल काची (VCK) और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) के प्रतिनिधियों को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं, AIADMK के बागी नेताओं को कैबिनेट में जगह मिलने की संभावना नहीं है।

TVK के सीनियर नेता और मंत्री आधव अर्जुना ने कांग्रेस, VCK और IUML से सरकार में शामिल होने की अपील की। उन्होंने इसे

सरकार की अहम एडवाइजरी

'इंजेक्शन या उपचार में किसी भी कॉस्मेटिक उत्पाद के इस्तेमाल की अनुमति नहीं'

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत सरकार के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत आने वाले केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) ने साफ किया है कि इंजेक्शन के रूप में दिए जाने वाले कॉस्मेटिक उत्पाद कानून के तहत कॉस्मेटिक की परिभाषा में नहीं आते और इन्हें उपभोक्ताओं, पेशेवरों या एस्थेटिक क्लीनिकों द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं है। सीडीएससीओ की यह एडवाइजरी ऐसे समय में आई है जब देशभर में ब्यूटी क्लीनिकों और वेलनेस सेंटरों में इंजेक्टेबल एस्थेटिक प्रक्रियाओं को कॉस्मेटिक उपचार के रूप में तेजी से बढ़ावा दिया जा रहा है।

कॉस्मेटिक श्रेणी में आते हैं ये उत्पाद: ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अनुसार, कॉस्मेटिक का मतलब ऐसी चीजों से है जिन्हें शरीर पर रगड़ा, डाला, छिड़का या लगाया जाता है। इनका मकसद शरीर की सफाई करना, सुंदरता बढ़ाना या रूप को आकर्षक बनाना होता है।

कॉस्मेटिक उत्पादों की बिक्री और वितरण 'कॉस्मेटिक नियम 2020' के तहत नियंत्रित होते हैं। सरकार ने साफ किया है कि जो उत्पाद इंजेक्शन के रूप में दिए जाते हैं, वे कॉस्मेटिक की श्रेणी में नहीं आते। कोई भी ग्राहक, पेशेवर व्यक्ति या ब्यूटी क्लिनिक किसी भी कॉस्मेटिक को इंजेक्शन की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। कॉस्मेटिक केवल बाहरी इस्तेमाल के लिए होते हैं।

लेबलिंग को लेकर भी कड़े नियम

लेबलिंग को लेकर भी कड़े नियम बताए गए हैं। कोई भी कॉस्मेटिक कंपनी अपने उत्पाद को लेकर झूठे या भ्रामक दावे नहीं कर सकती। साथ ही, कोई भी व्यक्ति कंपनी के कंटेनर या लेबल पर लिखी जानकारी को बदल नहीं सकता और न ही उसे मिटा सकता है।नियमों के अनुसार, कॉस्मेटिक उत्पादों में प्रतिबंधित सामग्री का इस्तेमाल करना, लेबल पर गलत जानकारी देना या इनका उपयोग किसी बीमारी के इलाज के लिए करना कानून का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई कॉस्मेटिक को इंजेक्शन के जरिए शरीर में डालता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई होगी।ड्रग कंट्रोलर जनरल ने जनता से अपील की है कि अगर वे कहीं भी नियमों का ऐसा उल्लंघन देखें, तो इसकी जानकारी तुरंत अधिकारियों को कर सकते हैं या राज्य की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को बता सकते हैं। यह नोटिस सभी ग्राहकों, निर्माताओं और ब्यूटी एक्सपर्ट्स के लिए जारी किया गया है।

फूलों की खुशबू से महकेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, अलग-अलग किस्म के लगेंगे 17,000 पौधे; नोएडा एयरपोर्ट से भी जुड़ेगा

फरीदाबाद, एजेंसी। अपने नाम के समरूप ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे फूलों की सुगंध और हरियाली से हर वक्त तरोताजा दिखेगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ हरित पट्टी और इसकी फेंसिंग व रेलिंग पर सुगंधित पौधे रोपेगा।

वनस्पतियों में सबसे ज्यादा कार्बन डाईआक्साइड अवशोषित करने वाले बांस के पौधे भी इसके दोनों तरफ दिखाई देंगे। पौधारोपण का कार्य आने वाले मानसून के दस्तक देते ही शुरू हो जाएगा। पौधों में विभिन्न किस्म के 17 हजार पौधे लगेंगे। सुगंधित फूलों में करीब पांच से छह तरीके की बेल लगाई जाएगी।

बताया कि 32 किलोमीटर लंबे ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण सेक्टर-65 में बन रहे डीएनडी फरीदाबाद सोहना एक्सेस कंट्रोल प्वाइंट से शुरू हो रहा है। यह केजीपी को कनेक्ट देते हुए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक जाएगा।

मंत्री नितिन गडकरी को दी थी जानकारी

मंगलवार को इस एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का निरीक्षण करने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी फरीदाबाद पहुंचे थे। निरीक्षण स्थल पर एनएचएआई अधिकारी मौजूद थे। चर्चा के दौरान एनएचएआइ अधिकारियों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को मानसून से पहले पौधरोपण अभियान शुरू किए जाने की जानकारी नितिन गडकरी को दी थी।

● इन सुगंधित फूलों की खुशबू से महकेगा एक्सप्रेसवे

एक्सप्रेसवे की फेंसिंग-रेलिंग के साथ कचनार, चंपा, मधुकामिनी, हारसिंगार, रात की रानी और चमेली की बेल लगेंगी। हारसिंगार रात में खिलने वाला बेहद सुगंधित फूल है। सफेद-केसरिया रंग वाले फूल रात को खिलकर सुबह जमीन पर गिर जाते हैं। इसकी खुशबू दूर तक महकती है। रात या सुबह के समय यात्रा करने वाले ड्राइवरों-यात्रियों को ताजगी का एहसास कराएगी। कचनार के फूल-फूल वसंत और गर्मियों में भीनी और मनमोहक खुशबू बिखेरते हैं। एक्सप्रेसवे के डिवाइडर पर लगने वाले चंपा लोकप्रिय फूलों में शुमार है। इसके सफेद या पीले फूलों में ताज़ा और मीठी खुशबू होती है।

● एक्सप्रेसवे पर सीओ-2 को अवशोषित करेंगे बांस के पेड़

केंद्र सरकार ने पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन शुरू किया है। 2017 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन किया गया था। इसके तहत गैर-वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को पेड़ों की श्रेणी से बाहर करके उसे घास माना गया। वनस्पति वैज्ञानिकों ने स्पष्ट किया है कि बांस का पौधा सबसे तेजी से बढ़ता है। यह एक दिन में करीब 120 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। अहम बात यह है कि बांस सामान्य पेड़ों की तुलना में 35 फीसद अधिक ऑक्सीजन पैदा करता है। एक हेक्टेयर बांस का जंगल सालाना करीब 17 टन कार्बन डाईआक्साइड को अवशोषित कर सकता है। ऐसे में एक्सप्रेसवे के साथ लगने वाले बांस के पेड़ प्रदूषण को नियंत्रित करने में कारगर साबित होंगे। ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ हरियाली व फूल देखकर सफर करने वाले यात्री इस पर यात्रा का सुखद अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। एनएचएआइ का लक्ष्य है कि दिल्ली एनसीआर में जैसे ही मानसून दस्तक देगा, एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 17 हजार पौधे लगाने का अभियान चालू हो जाएगा।

सीएम भजनलाल शर्मा का डूंगरपुर दौरा, बीएपी के गढ़ में साधेंगे आदिवासी समीकरण

उदयपुर, एजेंसी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार से दो दिवसीय डूंगरपुर दौरे पर रहेंगे। उनका यह दौरा प्रशासनिक समीक्षा से अधिक आदिवासी राजनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री सीधे भारत आदिवासी पार्टी (बीएपी) के सबसे मजबूत गढ़ चौरासी विधानसभा और सांसद राजकुमार रोत के गृह क्षेत्र धंबोला पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री शाम को जिला कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की बैठक लेकर बिजली, पानी और लंबित विकास कार्यों की समीक्षा करेंगे। इसके बाद वे धंबोला स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक

विद्यालय में रात्रि चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनेंगे और मौके पर समाधान के निर्देश देंगे। मुख्यमंत्री रात को स्थानीय आदिवासी परिवार के घर भोजन और रात्रि विश्राम भी करेंगे। राजनीतिक जानकारों के अनुसार हाल ही में हुए उपचुनाव में बीएपी की जीत का अंतर घटकर 20 हजार वोटों तक सीमित रह गया था, जबकि विधानसभा चुनाव 2023 में राजकुमार रोत करीब 69 हजार वोटों से जीते थे। ऐसे में भाजपा अब आदिवासी क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। डूंगरपुर और वागड़ क्षेत्र में पिछले एक महीने से जारी अघोषित बिजली कटौती भी बड़ा मुद्दा बनी हुई है। कांग्रेस और बीएपी लगातार सरकार पर हमलावर हैं। विशेषज्ञों के अनुसार क्षेत्र में 440 केवी जीएसएस की जरूरत लंबे समय से महसूस की जा रही है।

सीएम का मिनट-टू-मिनट कार्यक्रम : 3:30 से 5:30 बजे: कलेक्ट्रेट में अधिकारियों की समीक्षा बैठक

6:45 से 9:30 बजे: धंबोला में रात्रि चौपाल और जनसुनवाई । रात 10 बजे: आदिवासी परिवार के घर भोजन व रात्रि विश्राम। सुबह 6 से 9 बजे: मॉर्निंग वॉक के दौरान आमजन से सीधा फीडबैक।

गाजियाबाद में नहीं दिखा हड़ताल का असर, सड़कों पर दौड़ रहे ऑटो-टैक्सी और कैब

गाजियाबाद, एजेंसी। ट्रांसपोर्ट यूनियन की ओर से अपनी मांगों को लेकर तीन दिन (21 मई से 23 मई) तक चक्का जाम की अपील की है। इसका असर फिलहाल गाजियाबाद में कम दिख रहा है। ऑटो और कैब सड़क पर चल रही हैं, सिर्फ लोडिंग वाहनों के लिए चक्का जाम की अपील की गई है। हालांकि, हाईवे पर लोडिंग वाहन भी चलते दिख रहे हैं। गाजियाबाद ट्रांसपोर्ट यूनियन के पदाधिकारी सौदान सिंह गुर्जर ने बताया कि अभी वाहन चालकों को समझाया जा रहा है, जो वाहन बाहर गए थे वह वापस आ रहे हैं। बताया कि जो वाहन जिले में आए हैं, उनको तीन दिन रुकने के लिए कहा गया है। जरूरत पड़ी तो शुक्रवार को सड़क पर जाम भी लगाया जाएगा।

सिर्फ जन्मजात अमेरिकी ही संभालें सत्ता' अमेरिकी संसद ने प्रस्ताव पेश; जमकर हो रहा विरोध

वाशिंगटन, एजेंसी। अमेरिका में प्राकृतिक रूप से नागरिकता हासिल करने वाले लोगों के अधिकारों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। रिपब्लिकन सांसद नैन्सी मेस ने एक संवैधानिक संशोधन प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें प्राकृतिक रूप से अमेरिकी नागरिक बने लोगों को कांग्रेस सदस्य, संघीय न्यायाधीश और सीनेट की पुष्टि वाले महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त होने से रोकने की मांग की गई है। इस प्रस्ताव को लेकर डेमोक्रेटिक नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और इसे नस्लवादी, घृणित और विदेशी मूल के लोगों के खिलाफ बताया है। साउथ कैरोलिना की सांसद मेस ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय से लंबित संवैधानिक संशोधन पेश किया है। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका के

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए पहले से ही नेचुरल बॉर्न सिटिजन यानी जन्म से अमेरिकी नागरिक होना जरूरी है, इसलिए यही नियम कांग्रेस, संघीय अदालतों और सीनेट से मंजूर होने वाले पदों पर भी लागू होना चाहिए। मेस ने अपने पोस्ट में डेमोक्रेटिक सांसदों इल्हान उमर, प्रमिला जयपाल और श्री थानेदार की तस्वीरें भी साझा कीं। इनमें उमर सोमालियाई मूल की अमेरिकी हैं, जबकि जयपाल और थानेदार भारतीय मूल के नेता हैं।

लोगों की निष्ठा अमेरिका के प्रति होनी चाहिए- मेस: मेस ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका के कानून लिखने वाले, न्यायाधीशों की पुष्टि करने वाले और दुनिया के सामने अमेरिका का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की निष्ठा सिर्फ अमेरिका के प्रति होनी चाहिए, किसी दूसरे देश के प्रति नहीं। उन्होंने खास तौर पर इल्हान उमर का जिक्र करते हुए कहा कि कुछ नेताओं की वफादारी अमेरिका से बाहर दिखाई देती है।

सब पर पड़ेगा इस प्रस्ताव का असर: हालांकि, इस प्रस्ताव का असर केवल डेमोक्रेट्स तक सीमित नहीं रहेगा। अमेरिका की कांग्रेस में ऐसे 26 सदस्य हैं जो विदेश में जन्मे हैं, जिनमें कुछ रिपब्लिकन सांसद भी शामिल हैं।

हो रही कड़ी आलोचना: डेमोक्रेटिक सांसदों ने इस प्रस्ताव की कड़ी आलोचना की। भारतीय मूल की सांसद प्रमिला जयपाल ने इसे संकीर्ण सोच, विदेशी विरोधी मानसिकता और अमेरिका के इतिहास का अपमान बताया। उन्होंने कहा कि यह विधेयक नस्लवाद से प्रेरित है और कांग्रेस में इसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। भारतीय मूल के सांसद श्री थानेदार ने भी मेस पर तीखा हमला बोला।

भारत-इटली के बीच व्यापार और तकनीक पर बड़ा समझौता, 2029 तक 2000 अरब से अधिक का लक्ष्य

रोम, एजेंसी। भारत और इटली के द्विपक्षीय संबंधों को एक नया और बेहद मजबूत आयाम मिला है। इस संबंध में विदेश मंत्रालय के सचिव सीबी जॉर्ज ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि हाल ही में भारत-यूरोपीय संघ के बीच संपन्न हुए मुक्त व्यापार समझौते की वार्ताओं ने दोनों देशों के व्यापारिक और आर्थिक रिश्तों को एक नई ऊर्जा दी है। इस ऐतिहासिक बैठक के बाद, दोनों देशों ने साल 2029 तक आपसी द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब यूरो यानी करीब 2,241.85 अरब रुपये तक पहुंचाने का एक बड़ा और महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है। इसके साथ ही, दोनों देशों ने निजी क्षेत्रों को एक साथ आने, मजबूत साझेदारी बनाने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित करने के लिए निवेश करने के लिए भी प्रोत्साहित किया है। सीबी जॉर्ज ने बताया कि रोम में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने वैश्विक सुरक्षा के मुद्दों पर खुलकर बात की। दोनों नेताओं ने मिलकर आतंकवाद और हिंसक उग्रवाद के सभी रूपों की कड़े शब्दों में निंदा की। इस दौरान सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ एक बेहद सख्त और स्पष्ट संदेश दिया गया। रक्षा और सुरक्षा के मोर्चे पर दोनों देशों ने एक सुर में आतंकवाद को उखाड़ फेंकने का संकल्प दोहराया है। इस द्विपक्षीय वार्ता के दौरान तकनीक और नवाचार के क्षेत्र में सहयोग को एक नए स्तर पर ले जाया गया। बैठक के दो सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए। महत्वपूर्ण खनिजों पर समझौता ज्ञापन: दोनों देशों ने इस पर हस्ताक्षर कर भविष्य की तकनीक को सुरक्षित करने की दिशा में कदम बढ़ाया। नवाचार केंद्र की स्थापना: भारत में एक आधुनिक इनोवेशन सेंटर स्थापित करने का एक बड़ा निर्णय लिया गया।

पीएम मोदी का 5 देशों का दौरा पूरा: रोम से स्वदेश रवाना; बोले- आतंक वित्तपोषण के खिलाफ इटली का सहयोग वैश्विक नजीर

रोम (इटली), एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पांच देशों के आधिकारिक दौरे को पूरा करते हुए बुधवार को इटली के रोम से भारत के लिए प्रस्थान किया। यह दौरा भारत की वैश्विक कूटनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इटली यात्रा में रिश्तों को मिली नई मजबूती: प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी इटली यात्रा को बेहद सफल बताते हुए कहा कि उनकी चर्चा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर केंद्रित रही। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा कि भारत और इटली ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप तक पहुंचाने का निर्णय लिया है, जिससे आने वाले समय में दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी। पीएम मोदी ने इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मटेरेला से मुलाकात कर व्यापार, निवेश, संस्कृति, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, महत्वपूर्ण खनिज, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तृत चर्चा की।

आतंक के वित्तपोषण के खिलाफ भारत इटली की पहल वैश्विक नजीर: मोदी: पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद मानवता के लिए एक गंभीर चुनौती है और भारत-इटली दोनों इस बात पर एकमत हैं। आतंकवाद के वित्तपोषण के खिलाफ हमारी पहल ने पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है। पीएम मोदी ने कहा, भारत और इटली ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जिम्मेदार लोकतंत्र न केवल आतंकवाद की निंदा करते हैं, बल्कि इसके वित्तीय नेटवर्क को बाधित करने के लिए ठोस कदम भी उठाते हैं। पीएम ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया संकट के बारे में कहा कि हम यूक्रेन, पश्चिम

एशिया और अन्य तनावों के संबंध में लगातार एक-दूसरे के संपर्क में हैं। भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है कि सभी समस्याओं का समाधान संवाद और कूटनीति से होना चाहिए। इटली की पीएम जियोर्जिया मेलनी के साथ वार्ता के बाद साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी ने कहा, दोनों देशों के रक्षा उद्योगों के साथ-साथ हमारी सेनाओं में भी सहयोग बढ़ रहा है।

इटली दौरे की बड़ी उपलब्धियां: दोनों देशों के संबंध को विशेष रणनीतिक साझेदारी में बदलने से द्विपक्षीय संबंध तेजी से आगे बढ़ेगा। भारत-इटली रक्षा औद्योगिक रोडमैप: रक्षा सहयोग और रक्षा उत्पादन तंत्र मजबूत होगा दुर्लभ खजिनों के क्षेत्र में सहयोग का एमओयू से खोज-खनन-उत्पादन में तेजी। आधुनिक तकनीक और निवेश में सहयोग बढ़ेगा। ईडी-इटली के वित्तीय निगरानी विभाग में सहयोग से टैक्स संबंधी अपराधों, धनशोधन और आतंकवाद के खिलाफ फंडिंग पर मिलकर काम होगा। भारत-इटली में 2027 को संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने का समझौता: दोनों देशों में सांस्कृतिक आदान-प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। भारतीय नर्सों को काम के लिए इटली भेजने का समझौता: इससे भारतीय स्वास्थ्य क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। दुनिया में भारतीय कार्यबल की गुणवत्ता को मान्यता। गुजरात के लोथल में नेशनल मेरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स निर्माण के एमओयू से भारतीय सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण होगा। उच्च शिक्षा और शोध में सहयोग का रोडमैप: शोध की गुणवत्ता, औद्योगिक संपर्क और आधुनिक शिक्षण का तंत्र विकसित होगा। क्षमता निर्माण होगा। समुद्री परिवहन क्षेत्र में सहयोग के लिए एमओयू से समुद्री बुनियादी ढांचा मजबूत होगा।

तस्वीरों में देखें पीएम मोदी का इटली दौरा: दोनों देशों ने संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना 2025-29 की प्रगति की समीक्षा की और व्यापार, निवेश, तकनीक, रक्षा, ब्लू इकोनॉमी, कनेक्टिविटी, शिक्षा और जन-से-जन संबंधों जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति जताई। इटली सरकार ने भी इस यात्रा को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि भारत और इटली के संबंध अब अपने सबसे उच्च स्तर पर पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्रालय के आधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी इस दौरे को बेहद सफल बताया।

डिफॉल्टरों के फोन लॉक नहीं कर सकेंगे बैंक, रिकवरी एजेंटों की मनमानी पर रोक; ग्राहकों को बड़ी राहत

मुंबई, एजेंसी। आरबीआई ने बुधवार को कहा कि बैंक पर्सनल, कार या होम लोन की रिकवरी के लिए डिफॉल्टर के मोबाइल फोन को डिसेबल या प्रतिबंधित नहीं कर सकते हैं। हालांकि, बैंकों को उस मोबाइल डिवाइस को प्रतिबंधित या डिसेबल करने की अनुमति होगी, जिसे बैंक ने स्वयं फाइनेंस किया है। केंद्रीय बैंक इन नियमों को 1 अक्टूबर, 2026 से लागू करने का प्रस्ताव कर रहा है। केंद्रीय बैंक ने लोन की बकाया राशि की रिकवरी और रिकवरी एजेंसियों को काम पर रखने के मामलों से जुड़े सख्त

नियम प्रस्तावित किए है। ये नियम उधारकर्ताओं के उत्पीड़न की शिकायतों के बीच लाए गए हैं, जिसमें इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के जरिये उत्पीड़न और गाली-गलौज का इस्तेमाल शामिल है। आरबीआई ने प्रस्ताव दिया है, कोई भी बैंक ऐसा कोई तकनीक आधारित तरीका नहीं अपनाएगा, जो किसी उधारकर्ता के मोबाइल डिवाइस की कार्यक्षमता को प्रभावित करे। बैंक ऐसा तभी कर सकेंगे जब उसे डिवाइस के फाइनेंस से जुड़े लोन की बकाया राशि की रिकवरी करनी हो। इस मामले में भी बैंक तब तक डिवाइस को ब्लॉक नहीं कर सकेंगे जब तक कि संबंधित लोन 90 दिनों से ज्यादा समय से बकाया नहीं हो गया हो। आरबीआई ने कहा कि गलत तरीके से प्रतिबंध लगाने या उसे हटाने में देरी होने पर बैंक को उधारकर्ता को उस समय तक 250 रुपये प्रति घंटे की दर से मुआवजा देना होगा, जब तक कि उस गलत कार्रवाई को ठीक नहीं कर दिया जाता है। केंद्रीय बैंक ने लोन की रिकवरी और रिकवरी एजेंटों को काम पर रखने के मामलों में भी संशोधित मसौदा निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को अपने कर्मचारी/रिकवरी एजेंट द्वारा लोन की बकाया राशि की रिकवरी के लिए उधारकर्ता/गारंटर को की गई काल का समय और संख्या रिकार्ड करनी चाहिए।

फर्जी वीजा के साथ तीन लोग गिरफ्तार, इराक जाने के लिए पहुंचे थे एयरपोर्ट

जयपुर, एजेंसी। जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर फर्जी पर्यटक वीजा के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए तीनों लोग ईराक जाने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचे थे। जयपुर हवाई अड्डा थाना पुलिस के अनुसार गिरफ्तार किए गए लोगों में उत्तरप्रदेश में अंबेडकर नगर के देवरिया बुजुर्ग निवासी सुरेश कुमार, बिहार में पूर्वी चंपारण निवासी रूपेश यादव और बिहार में ही पटना जिले के धनौती गांव निवासी आलोक कुमार सिंह शामिल है। जयपुर पुलिस उपायुक्त रंजीता शर्मा ने बताया कि पकड़े गए तीनों लोग मंगलवार रात अंतरराष्ट्रीय उड़ान से ईराक जाने की तैयारी कर रहे थे। दस्तावेजों की जांच में इनके पर्यटक वीजा फर्जी मिलने पर उन्हे पकड़ कर पूछताछ की गई तो उन्होंने वीजा फर्जी होने की बात स्वीकार की है। तीनों लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के तहत हवाई अड्डा पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं फर्जी वीजा बनाकर लोगों को विदेश भेजने के लिए काम में कोई गिरोह तो सक्रिय नहीं है। जयपुर पुलिस ने बिहार और उत्तरप्रदेश पुलिस से भी इस संबंध में संपर्क साधा है।

एक्सीडेंट में घायल 8 साल के बच्चे को मुआवजे से इनकार, कोर्ट ने दावा खारिज कर बोला- सिर्फ चार्जशीट ही काफी नहीं

नईदिल्ली, एजेंसी। सुंदर नगरी में सड़क हादसे में घायल आठ साल के बच्चे को मुआवजा देने से इनकार करते हुए कड़कड़डूमा अदालत ने कड़ी टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि केवल चार्जशीट के आधार पर जिम्मेदारी तय नहीं की जा सकती। अदालत ने साफ कहा कि दावों को साबित करने के लिए विश्वसनीय और ठोस साक्ष्य अनिवार्य हैं। ऐसा नहीं करने पर हर मामले में बिना जांच के मुआवजा देना पड़ेगा। दिल्ली मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूरल ने 2023 के एक सड़क हादसे से जुड़े मामले में यह फैसला सुनाया। ड्राइविंग में लापरवाही नहीं साबित हो सकी पीठासीन अधिकारी विजय कुमार झा ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहे कि बच्चे को गंभीर चोटें लापरवाह और तेज रफ्तार ड्राइविंग के कारण लगी थीं। मामला सुंदर नगरी का है, जहां मार्च

2023 में आठ वर्षीय आतिफ अपने पिता के साथ सड़क पार कर रहा था। आरोप था कि एक मोटरसाइकिल चालक ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए उसे टक्कर मारी। साक्ष्यों और गवाहियों में सामने आए विरोधाभाष इस मामले में नंद नगरी थाने में केस दर्ज कर चार्जशीट भी दायर की गई थी। ट्रिब्यूनल को साक्ष्यों और गवाहियों में कई विरोधाभास मिले। अस्पताल के रिकॉर्ड में यह नहीं पाया गया कि बच्चे के पिता उसे अस्पताल लेकर गए थे। अदालत ने कहा कि यदि केवल चार्जशीट के आधार पर मुआवजा दिया जाए, तो न्यायिक प्रक्रिया का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। साथ ही जांच एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा गया कि महत्वपूर्ण गवाहों और परिस्थितियों की ठीक से जांच नहीं की गई।

ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि हादसे में शामिल बताए गए वाहन की पहचान संदिग्ध है और संभावना है कि उसे बाद में मामले में प्लांट किया गया हो। इसके बाद मुआवजे की मांग को खारिज कर दिया गया।

क्या आप 'बापू' से कुछ पूछना चाहते हैं? तो चले आइए प्रधानमंत्री संग्रहालय; महात्मा गांधी का एआई अवतार लॉन्च

नई दिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री संग्रहालय में आने वाले आगंतुक अब महात्मा गांधी के कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से संचालित 3डी अवतार से बातचीत कर सकते हैं। संग्रहालय ने बुधवार को एआई-संचालित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया, जो अत्याधुनिक तकनीक के माध्यम से बापू की आत्मा को जीवंत करती है। एआई-संचालित इंटरैक्टिव होलोबाक्स इंस्टालेशन प्रधानमंत्री संग्रहालय में इस प्रकार की तीसरी प्रदर्शनी है। 25 मार्च को दी थी कि संग्रहालय ने मई के अंत में एआई आधारित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के होलोबॉक्स को शुरू करने की योजना बनाई थी।

भूतपूर्व सैनिक चौपाल आयोजित, कलेक्टर ने जिले के विकास कार्यों में सहभागिता का किया आह्वान

मीडिया ऑडिटर, सीधी (निप्र)। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित भूतपूर्व सैनिक चौपाल में जिले के भूतपूर्व सैनिकों के साथ संवाद स्थापित कर उन्हें जिले के विकास एवं जनकल्याणकारी अभियानों में सक्रिय सहभागिता के लिए आमंत्रित किया गया कलेक्टर विकास मिश्रा ने कहा कि भूतपूर्व सैनिकों का अनुशासन, नेतृत्व क्षमता सेवा भावना और समाज के प्रति समर्पण जिले के विकास कार्यों को नई दिशा दे सकता है उन्होंने कहा कि सैनिक केवल सीमाओं की रक्षा तक सीमित नहीं हैं बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी समाज निर्माण में उनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकती है चौपाल में कलेक्टर ने भूतपूर्व सैनिकों से स्वास्थ्य, शिक्षा, पोषण, रोजगार सृजन, नशामुक्ति एवं सामाजिक जागरूकता अभियानों में सक्रिय भागीदारी का आह्वान किया। उन्होंने विशेष रूप से टीबी मुक्त भारत अभियान में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि भूतपूर्व सैनिक अपने क्षेत्र के टीबी मरीजों के संपर्क में रहकर यह सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं कि उनका उपचार नियमित और सही तरीके से हो रहा है उन्होंने भूतपूर्व सैनिकों से निक्षय मित्र बनकर टीबी उन्मूलन अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने की अपील की कलेक्टर ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य कुसमी क्षेत्र में सिकल सेल एनीमिया की स्क्रीनिंग एवं उपचार की निगरानी अत्यंत आवश्यक है जिसमें भूतपूर्व सैनिकों का सहयोग उपयोगी सिद्ध हो सकता है इसी प्रकार गंभीर कुपोषित बच्चों के पोषण स्तर में सुधार उनके परिवारों से सतत संवाद और पोषण संबंधी व्यवहार परिवर्तन में भी उनकी भूमिका महत्वपूर्ण रहेगी शिक्षा के क्षेत्र में कलेक्टर ने भूतपूर्व सैनिकों से आदिवासी छात्रावासों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखने तथा छात्र-छात्राओं को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की निगरानी एवं मार्गदर्शन में सहयोग करने का आग्रह किया साथ ही युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं एवं सैन्य सेवाओं के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता पर जोर दिया उन्होंने बताया कि जिले में युवाओं के मार्गदर्शन हेतु सीधी में संकल्प कोचिंग चुरहट में श्रमोदय कोचिंग संचालित हैं, जबकि सिहावल में कौटिल्य कोचिंग एवं मझौली में अग्निवीर कोचिंग शीघ्र प्रारंभ की जा रही हैं इन संस्थानों में भूतपूर्व सैनिकों के अनुभव एवं मार्गदर्शन से युवाओं को बड़ा लाभ मिल सकता है कलेक्टर ने स्वरोजगार एवं स्थानीय रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी भूतपूर्व सैनिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व सैनिक अपने अनुभव और नेतृत्व क्षमता के आधार पर स्वरोजगार इकाइयां स्थापित कर स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं इसके साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने तथा सामुदायिक सहभागिता से आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर भी बल दिया गया नशामुक्त समाज के निर्माण पर जोर देते हुए कलेक्टर ने कहा कि भूतपूर्व सैनिक समाज में अनुशासन और सकारात्मक जीवनशैली के प्रेरक हैं ऐसे में वे नशे के विरुद्ध जनजागरूकता अभियान में प्रभावी भूमिका निभाकर युवाओं को सकारात्मक दिशा दे सकते हैं चौपाल में उपस्थित भूतपूर्व सैनिकों ने जिला प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे समाजहित में महत्वपूर्ण कदम बताया उन्होंने स्वास्थ्य शिक्षा, पोषण, टीबी उन्मूलन नशामुक्ति, युवाओं के मार्गदर्शन एवं रोजगार सृजन सहित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं और अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग देने की सहमति व्यक्त की इस अवसर पर जिला सैनिक कल्याण अधिकारी ग्रुप कैप्टन सिद्धार्थ श्रीवास्तव, वीर नारी, जिला प्रशासन के संबंधित अधिकारी एवं भूतपूर्व सैनिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे।

राशन दुकान से अतिरिक्त खाद्यान्न जब्त, विक्रेता पर केस आवश्यक वस्तु अधिनियम में केस

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। सिंगरौली जिले के माडा थाना क्षेत्र स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान कर्मुआराजा में खाद्यान्न स्टॉक में बड़ी अनियमितता मिली है। प्रशासन ने दुकान से 3 लाख 61 हजार 388 रुपए की कीमत का अतिरिक्त राशन जब्त किया है। गुरुवार को इस मामले में दुकान विक्रेता संजय कुमार पाण्डेय के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की गई स्टॉक मिलान में अधिक मिला गेहूं, चावल और नमक कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सम्मी कुमार पटले के भौतिक सत्यापन में पाया गया कि दुकान में उपलब्ध राशन पीओएस मशीन में दर्ज मात्रा से कहीं अधिक था। मिलान के दौरान 85.91 क्विंटल गेहूं, 59.50 क्विंटल चावल और 22.65 क्विंटल नमक अतिरिक्त पाया गया। इसे सरकारी राशन की हेराफेरी और वितरण प्रणाली में गंभीर लापरवाही माना गया है आयुक्त और कलेक्टर के निरीक्षण में खुलासा यह गड़बड़ी रीवा संभाग आयुक्त और सिंगरौली कलेक्टर के भ्रमण के दौरान 14 मई 2026 को किए गए औचक निरीक्षण में सामने आई थी जांच रिपोर्ट के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी माडा ने कार्रवाई के आदेश जारी किए प्रशासन ने बताया कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में गड़बड़ी करने वालों पर सख्त नजर रखी जा रही है आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत केस माडा थाना पुलिस ने आरोपी विक्रेता संजय कुमार पाण्डेय पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 और 7 के तहत अपराध क्रमांक 0336/2026 दर्ज किया है। पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू कर दी है जब्त किए गए खाद्यान्न को लेकर विक्रेता से पूछताछ की जा रही है कि यह अतिरिक्त स्टॉक दुकान में कैसे पहुंचा।

स्कूल परिसर में चल रहा था नशे का कारोबार : डायरेक्टर गिरफ्तार, 208 शीशी नशीली कफ सिरप-आल्टो कार जब्त

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस ने गुरुवार दोपहर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक स्कूल परिसर में चल रहे अवैध कारोबार का खुलासा किया है पुलिस ने 208 शीशी नशीली कफ सिरप जब्त कर स्कूल के डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है स्कूल परिसर में दी गई दबिश कोतवाली और जमोड़ी पुलिस की संयुक्त टीम ने गजराज स्कूल परिसर में छापा मारा पुलिस को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि स्कूल के आसपास नशीली कफ सिरप बेची जा रही है यह भी सूचना थी कि स्कूल के कमरों का इस्तेमाल नशा रखने और सप्लाई करने के लिए किया जा रहा है थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय और दिव्य प्रकाश त्रिपाठी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की कार और कमरों से मिली कफ सिरप दबिश के दौरान अमरवाह निवासी अमन सिंह चौहान को मौके से गिरफ्तार किया गया तलाशी में स्कूल के कमरों और आरोपी की आल्टो कार क्रमांक MP18CA2926 से कुल 208 शीशी नशीली कफ सिरप बरामद हुई पुलिस के अनुसार इसकी कीमत करीब 52 हजार रुपए है पुलिस ने जब आरोपी से वैध दस्तावेज मांगे तो वह कोई कागजात पेश नहीं कर सका कई अन्य आरोपियों की तलाश जारी पूछताछ में आरोपी ने स्वीकार किया कि वह अपने साथियों के साथ लंबे समय से नशे का कारोबार चला रहा था मामले में आशू केवट, प्रिंस मिश्रा, अम्बिकेश सिंह गोंड नवीन नामदेव और अमन सोधिया के नाम भी सामने आए हैं पुलिस इन आरोपियों की तलाश कर रही है स्कूल की मान्यता होगी खत्म पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट और मध्य प्रदेश ड्रग कंट्रोल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है स्कूल परिसर का इस्तेमाल अवैध गतिविधियों में होने के कारण संबंधित स्कूल की मान्यता समाप्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

ओवरलोड गेहूं से भरा ट्रक पलटा :लोग कहते रहे 'पलट जाएगी गाड़ी' लाइव वीडियो में हुआ हादसा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सीधी जिले के मझौली में गुरुवार सुबह एक ओवरलोड गेहूं से भरा ट्रक सड़क किनारे पलट गया यह घटना उस समय हुई जब मौके पर मौजूद लोग लगातार ट्रक के पलटने की आशंका जता रहे थे हादसे का लाइव वीडियो भी सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है जानकारी के अनुसार ट्रक मझौली उपार्जन केंद्र से गेहूं लेकर दडौरा तौल केंद्र जा रहा था बताया गया है कि ट्रक में क्षमता से कहीं ज्यादा गेहूं की बोरियां लदी थीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ट्रक की बॉडी से करीब 10 फीट ऊपर तक गेहूं भरा था जिसे रस्सियों से बांधा गया था। भारी वजन के कारण ट्रक सड़क पर चलते समय बार-बार एक तरफ झुक रहा था स्थानीय निवासी रामकिशोर पनिका ने बताया कि लोग ट्रक को देखकर पहले से ही आशंका जता रहे थे कि यह कभी भी पलट सकता है इसी दौरान कुछ लोग वीडियो बना रहे थे जिसमें साफ सुनाई दे रहा है कि प्रत्यक्षदर्शी कह रहे थे गाड़ी पलट जाएगी कुछ ही सेकंड बाद ट्रक असंतुलित होकर सड़क किनारे पलट गया हादसे के दौरान ट्रक के ड्राइवर और खलासी ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचा ली घटना के बाद दोनों मौके से चले गए ट्रक पलटने से गेहूं की बोरियां सड़क किनारे बिखर गईं और वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई गनीमत रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस वक्त वहां कोई राहगीर या अन्य वाहन मौजूद नहीं था जिससे बड़ा हादसा टल गया मझौली थाना प्रभारी ने इस पूरे मामले पर बताया कि घटना का वीडियो सामने आया है।

युवा संगम का आयोजन अब 26 मई को, मझौली में लगेगा रोजगार मेला

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जिला रोजगार अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि मध्यप्रदेश शासन के तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग द्वारा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार युवा संगम का आयोजन प्रत्येक माह के तीसरे मंगलवार को किया जाता है इस माह यह आयोजन 19 मई 2026 को प्रस्तावित था जिसे कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशानुसार परिवर्तित कर अब 26 मई 2026 को आयोजित किया जाएगा जिले के बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप के अवसर एक ही मंच पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में जिला रोजगार कार्यालय आईटीआई एवं जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र सीधी के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय युवा संगम संयुक्त रोजगार स्वरोजगार एवं अप्रेंटिसशिप मेले का आयोजन किया जा रहा है यह कार्यक्रम 26 मई 2026 को शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय मझौली, जिला सीधी के परिसर में प्रातः 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित होगा कार्यक्रम में देश प्रदेश एवं स्थानीय स्तर की निजी क्षेत्र की कंपनियां सहभागिता करेंगी जहां युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे इसके साथ ही स्वरोजगार संचालित विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर युवाओं को उद्यम स्थापना, स्वरोजगार योजनाओं एवं अप्रेंटिसशिप से संबंधित जानकारी प्रदान की जाएगी।

ऑटो ड्राइवर-महिला यात्री ने एक-दूसरे को पीटा, वीडीयो माजन मोड़ चौराहे पर अधिक किराया मांगने को लेकर हुआ विवाद

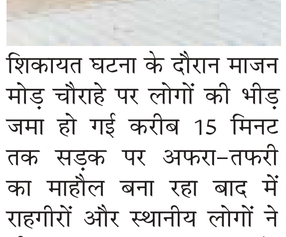

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। जिले के माजन मोड़ चौराहे पर गुरुवार सुबह ऑटो किराए को लेकर विवाद हो गया देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया और करीब 15 मिनट तक सड़क पर हंगामे की स्थिति बनी रही घटना कोतवाली और नवानगर थाना क्षेत्र की सीमा पर स्थित मुख्य चौराहे की है किराए को लेकर शुरू हुआ विवाद प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक ऑटो चालक महिला यात्री से तय से ज्यादा किराया मांग रहे थे इसी बात को लेकर महिला और चालक के बीच बहस शुरू हो गई कुछ देर बाद मौके पर मौजूद अन्य युवक भी विवाद में शामिल हो गए और सड़क पर धक्का-मुक्की व मारपीट होने लगी सोशल मीडिया पर सामने आए इस वीडियो में एक महिला और युवक एक-दूसरे का कॉलर पकड़कर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं अब तक नहीं हुई शिकायत घटना के दौरान माजन मोड़ चौराहे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई करीब 15 मिनट तक सड़क पर अफरा-तफरी का माहौल बना रहा बाद में राहगीरों और स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया मामले में किसी भी पक्ष की ओर से अब तक पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। हालांकि घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है स्थानीय लोगों का कहना है कि शहर में ऑटो चालकों द्वारा मनमाना किराया वसूले जाने की शिकायतें पहले भी सामने आती रही हैं लेकिन इस दिशा में अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है।

कलेक्टर ने जैविक संसाधन केंद्र का किया निरीक्षण, स्व-सहायता समूह की महिलाओं के जैविक उत्पादों को सराहा

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को सशक्त बनाने की दिशा में जिला प्रशासन लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में कलेक्टर विकास मिश्रा ने सीधी विकासखंड के ग्राम टिकटकला में एकीकृत कृषि क्लस्टर अंतर्गत संचालित जैविक संसाधन केंद्र का विस्तृत निरीक्षण किया निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने केंद्र में संचालित जैविक कृषि गतिविधियों का अवलोकन किया तथा मध्यप्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व-सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे जैविक उत्पादों की जानकारी प्राप्त की। महिलाओं द्वारा तैयार जीवामृत,बीजामृत, घनजीवामृत, नीमास्त्र, ब्रह्मास्त्र, दशपर्णी अर्क एवं वर्मीकम्पोस्ट (केंचुआ खाद) जैसे उत्पादों को देखकर उन्होंने उनके प्रयासों की सराहना की कलेक्टर ने समूह की महिलाओं से संवाद कर इन उत्पादों के निर्माण की प्रक्रिया, उपयोगिता और किसानों को मिलने वाले लाभों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के दुष्प्रभाव को देखते हुए जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है उन्होंने निर्देश दिए कि जैविक संसाधन केंद्र के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों एवं स्व-सहायता समूह की महिलाओं को जोड़ा जाए, ताकि वे प्राकृतिक खेती की तकनीकों को अपनाकर कृषि लागत कम करने के साथ उत्पादन और आय में वृद्धि कर सकें कलेक्टर ने इस पहल को और गति देने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में जैविक संसाधन केंद्र द्वारा निर्मित उत्पादों की बिक्री हेतु दुकान संचालन की अनुमति प्रदान की। साथ ही जनपद पंचायत सीईओ, कृषि विभाग एवं उद्यानिकी विभाग को निर्देशित किया कि महिलाओं द्वारा तैयार जैविक उत्पादों के प्रचार-प्रसार एवं विक्रय में सक्रिय सहयोग सुनिश्चित किया जाए केंद्र के प्रभारी एवं आजीविका मिशन के अधिकारियों ने कलेक्टर को केंद्र की उपलब्धियों और स्थानीय किसानों को दिए जा रहे प्रशिक्षण की जानकारी दी इस अवसर पर आजीविका मिशन के विकासखंड प्रबंधक अशोक पांडेय, आईएफसी नोडल मनोज मिश्रा, आईएफसी टीम, संसाधन केंद्र का स्टाफ एवं स्व-सहायता समूह की दीदियां उपस्थित रहीं।

तेज रफ्तार बस ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, चालक गंभीर रूप से घायल

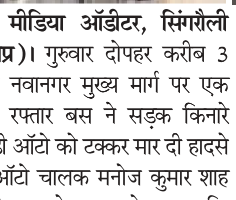

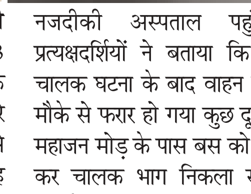

मीडिया ऑडीटर, सिंगरौली (निप्र)। गुरुवार दोपहर करीब 3 बजे नवानगर मुख्य मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस ने सड़क किनारे खड़ी ऑटो को टक्कर मार दी हादसे में ऑटो चालक मनोज कुमार शाह गंभीर रूप से घायल हो गए जबकि ऑटो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई जानकारी के अनुसार, टॉकीज रोड, बैढ़न निवासी मनोज कुमार शाह नाश्ता करने के लिए अपनी ऑटो सड़क किनारे खड़ी कर रहे थे। इसी दौरान जयंत की ओर से आ रही बस ने अचानक ऑटो को जोरदार टक्कर मारी। टक्कर इतनी भीषण थी कि ऑटो दो बार पलट गई और इसके परखच्चे उड़ गए हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत घायल चालक को ऑटो से बाहर निकाला और उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि बस चालक घटना के बाद वाहन लेकर मौके से फरार हो गया कुछ दूरी पर महाजन मोड़ के पास बस को खड़ा कर चालक भाग निकला सूचना मिलते ही नवानगर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच शुरू की पुलिस ने क्षतिग्रस्त ऑटो को अपने कब्जे में ले लिया है नवानगर थाना प्रभारी ने बताया कि सड़क हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस वैधानिक कार्रवाई में जुट गई। उन्होंने कहा कि फरार बस चालक की पहचान कर ली गई है और उसे जल्द हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी स्थानीय लोगों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर कड़ी निगरानी और उचित सुरक्षा उपाय करने की मांग की है।

पीएम जनमन एवं धरती आबा अभियान के तहत जनजातीय क्षेत्रों में विशेष जन चौपाल,

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। जनजातीय समुदायों तक शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री जनमन एवं धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान के अंतर्गत कुसमी विकासखंड के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष जन चौपालों का आयोजन किया जा रहा है। इन चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों को विभिन्न शासकीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ उनकी समस्याओं, आवश्यकताओं एवं सुझावों को सीधे सुनकर त्वरित समाधान की दिशा में कार्रवाई की जा रही है इसी क्रम में ग्राम पंचायत आमगांव के ग्राम बिड़ौरा में विशेष जन चौपाल आयोजित की गई जिसमें बीआरसीसी एवं नोडल अधिकारी अंगिरा प्रसाद द्विवेदी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों से सीधा संवाद कर शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, आजीविका राशन, पेंशन, रोजगार, पशुपालन एवं अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी साझा की गई। साथ ही पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया गया चौपाल के दौरान ग्रामीणों ने अपनी स्थानीय समस्याओं बुनियादी आवश्यकताओं एवं शासकीय योजनाओं से संबंधित सुझाव अधिकारियों के समक्ष रखे। अधिकारियों ने समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए तथा आश्वस्त किया कि प्राप्त मांगों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जाएगा अधिकारियों ने बताया कि पीएम जनमन एवं धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष अभियान का उद्देश्य दूरस्थ एवं विशेष रूप से कमजोर जनजातीय क्षेत्रों तक शासन की योजनाओं को पहुंचाना तथा समुदायों को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है।

महोत्सव की तैयारियों में प्रशासनिक सख्ती,मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का दो दिवसीय दौरा प्रस्तावित

मीडिया ऑडीटर, सीधी (निप्र)। सिंगरौली जिले में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रस्तावित दो दिवसीय दौरे और सिंगरौली महोत्सव की तैयारियों को लेकर प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं रीवा संभाग के आयुक्त बीएस जामोद और रीवा जोन के डीआईजी बुधवार देर रात सिंगरौली पहुंचे और गुरुवार सुबह कई कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण किया दोनों अधिकारियों ने राजमाता चुनकुमारी स्टेडियम, एनसीएल बाउंड्री क्षेत्र और एनटीपीसी कल्याण मंडप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, मंच निर्माण, यातायात प्रबंधन पार्किंग और अन्य मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की निरीक्षण में जिले के कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित कई विभागों के अधिकारी और कर्मचारी भी मौजूद रहे सिंगरौली महोत्सव का आयोजन 23, 24 और 25 मई को किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 23 मई को जिले में दो दिवसीय दौरे पर पहुंचेंगे। वे दोपहर में कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे और रात में जिले में ही विश्राम करेंगे 24 मई को मुख्यमंत्री जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे इस दौरान जिले की कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी प्रस्तावित है। समीक्षा और लोकार्पण कार्यक्रमों के बाद मुख्यमंत्री भोपाल के लिए रवाना होंगे निरीक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों ने भी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि आमजन की सुविधा और कार्यक्रम स्थलों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है निरीक्षण के बाद रीवा कमिश्नर बीएस जामोद ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि मुख्यमंत्री के दौरे से संबंधित सभी व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं उन्होंने सुरक्षा यातायात और आमजन सुविधाओं को प्राथमिकता के साथ व्यवस्थित करने पर जोर दिया ताकि महोत्सव और मुख्यमंत्री के दौरे को सफलता पूर्वक संपन्न किया जा सके प्रशासन ने संबंधित विभागों को कड़ी हिदायत दी है कि सभी कार्य समय पर पूरे किए जाएं।

तेल संकट के विरोधाभा

संपादकीय

बुलढाणा (महाराष्ट्र) में किसान धरने पर बैठ गए हैं। उन्हें पर्याप्त डीजल नहीं मिल पा रहा है। बिन डीजल के खेती करना नामुमकिन है। किसी जगह लोगों में मारपीट की नौबत आ गई है। एक जगह ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली और अपने-अपने डिब्बे, ड्रम लिए लोगों की लंबी-लंबी कतार लगी है। किसान पेट्रोल पंप के पास ही रात गुजारने, सोने को विवश हैं, लिहाजा मच्छरदानी तान कर बंदोबस्त कर रहे हैं। कोई पेट्रोल पंप ही बंद कर दिया गया है। तख्ती टांग दी गई है-पेट्रोल खत्म है और डीजल यहां नहीं बिकता। यह भारत देश की औसत तस्वीर है, हकीकत है, लेकिन केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी दावा कर रहे हैं कि देश में कच्चे तेल, नेचुरल गैस, रसोई गैस, पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है। ऐसे विरोधाभास में कब तक जिएगा आम भारतीय? कुछ आंकड़े गौरतलब हैं। इंडियन ऑयल कंपनी ने 95,000 करोड़ रुपए से अधिक, भारतीय पेट्रोलियम ने 65,000 करोड़ रुपए से अधिक, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने 48,000 करोड़ से अधिक और ओएनजीसी ने 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के मुनाफे कमाए हैं। आम उपभोक्ता को कितने सस्ते पेट्रोल-डीजल और एलपीजी मुहैया कराए गए? सरकार इस संदर्भ में बिल्कुल खामोश है। अलबत्ता पेट्रोलियम मंत्री जरूर रुदनावस्था में कहते रहे हैं कि अब भी तेल कंपनियों को रोजाना 750 करोड़ रुपए का घाटा है। पेट्रोल-डीजल के दाम जितने बढ़ाए गए हैं, उससे तो कंपनियों के नुकसान की 15 फीसदी ही भरपाई होगी। यदि पेट्रोल-डीजल 10 रुपए प्रति लीटर महंगे किए जाएंगे, तो घाटे की 50 फीसदी भरपाई हो सकती है। जब पेट्रो पदार्थ 17-18 रुपए महंगे होंगे, तो तेल कंपनियों का मुनाफा शुरू हो सकता है। आखिर ये मुनाफे किसके लिए हैं? क्या इनका एक हिस्सा आम उपभोक्ता से साझा नहीं करना चाहिए। जब देश में 70-72 डॉलर प्रति बैरल कच्चा तेल आ रहा था, तब भी कंपनियों ने पेट्रो पदार्थों के खुदरा दाम क्यों नहीं घटाए थे? ये भारत की सार्वजनिक उपक्रम वाली कंपनियां हैं, जो करदाता और शेयरधारक के पैसे से चलती हैं। किसी लाला की दुकानदारी नहीं है। बहरहाल भारत में तेल-संकट का दौर है और एक बड़ी तेल कंपनी करीब 2 लाख करोड़ रुपए अमरीका में निवेश करेगी! आपदा में भारतीय कंपनी अपने देश में नहीं, विदेश में निवेश करेगी, इससे कुरूप और भद्दा विरोधाभास क्या हो सकता है? इसी तरह दवाएं बनाने वाली एक बड़ी कंपनी भी करीब 2 लाख करोड़ रुपए अमरीका में ही निवेश करेगी। यह कैसा राष्ट्रवाद है? एक और विरोधाभास उल्लेखनीय है। मार्च-अप्रैल में भारत में 1.32 लाख करोड़ रुपए का कच्चा तेल आयात किया गया। फिर उसे रिफाइन करके 150 गरीब देशों को 52,826 करोड़ रुपए के पेट्रो पदार्थ निर्यात कर दिए गए।

कोरोना ऐसी महामारी नहीं युद्ध के कारण आर्थिक आपदा जरूर

संजय गोस्वामी

युद्ध ईरान - इजराइल अमेरिका का युद्ध में इतना गंभीर समस्या नहीं है कि कोरोना जैसी आपदा नहीं है उसमें जवान बूढ़े बच्चे सब मर रहें थे लाशों का अम्बार लगा था सनातन धर्म में इस आपदा से निपटने के लिए भौतिक सुखों का त्याग कर दीजिये आपदा ख़त्म हो जाएगी उस समय का माहौल अलग था अभी वैसा माहौल नहीं है वो महामारी थी ऐ आर्थिक संकट है भारत ऐसे भी भगवान राम को मानने वाला त्याग और संघर्ष वाले लोग हैं पेट्रोल ख़त्म हो गया तो इसमें चिंता करने की क्या जरुरत है आपका पैर जिन्दा है जब भगवान राम ने 14 वर्ष पैदल चलकर वन में बिताये तो क्या हम पैदल भी नहीं चल सकते सेहत के लिए पैदल चलना तो और सही है बहुत दूर है तो साइकिल से चल देंगे इससे भी सेहत और तंदरुस्त रहेगा बहुत लोग हैं तो बैलगाड़ी या टमटम से चलेंगे ज्यादा धुप है तो छाता या पेड़ की छाव में आराम कर लेंगे और भी दूर है तो नाव से नदी पार कर एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जा साकते है आज सभी को इस संकट की घड़ी में प्रभु राम से सिखने की जरुरत है प्रभु श्री राम का वनवास हिन्दू धर्म के प्रमुख ग्रंथ रामायण की एक अत्यंत महत्वपूर्ण घटना है। पिता राजा दशरथ के वचन की रक्षा के लिए श्री राम, अपनी पत्नी माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों के लिए वन गए। यहाँ इस संपूर्ण प्रसंग के मुख्य बिंदु दिए गए हैं: वनवास के मुख्य कारण कैकेयी के वरदान: राजा दशरथ ने अपनी प्रिय रानी कैकेयी को दो वरदान दिए थे। मंथरा के उकसाने पर, कैकेयी ने इन्हीं वरदानों का उपयोग करते हुए भरत के लिए अयोध्या का राजसिंहासन और श्रीराम के लिए 14 वर्ष का वनवास माँगा। पिता का वचन: राजा दशरथ ने अपने वचन का मान रखने के लिए भारी मन से राम को वन जाने का आदेश दिया। एक आदर्श पुत्र के रूप में राम ने सहर्ष पिता की आज्ञा का पालन किया वन गमन के दौरान प्रभु राम ने कई स्थानों की यात्रा की और ऋषियों-मुनियों से आशीर्वाद प्राप्त किया : तमसा नदी: अयोध्या छोड़ने के बाद पहली रात यहीं बिताई। श्रृंगवेरपुर: यहाँ उन्होंने गंगा नदी पार की और निषादराज गुह से भेंट की। चित्रकूट: यहाँ राम ने अपने भाई भरत से भेंट की, जो उन्हें वापस अयोध्या ले जाने आए थे। भरत ने राम की चरण-पादुका लेकर राज्य का संचालन किया। दंडकारण्य: चित्रकूट के बाद राम, सीता और लक्ष्मण ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के घने जंगलों, दंडकारण्य में लंबा समय बिताया। यहीं पर पंचवटी में उन्होंने अपनी कुटिया बनाई। किष्किंधा: यहीं पर हनुमान जी और सुग्रीव से उनकी भेंट हुई और सीता माता की खोज के लिए वानर सेना का गठन हुआ। वनवास के अंतिम चरण में लंकापति रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया, जिसके बाद प्रभु राम ने सुग्रीव और हनुमान जी की मदद से रावण की लंका पर आक्रमण किया। रावण वध: राम-रावण युद्ध में धर्म की जीत हुई और रावण का वध कर माता सीता को मुक्त कराया गया। अयोध्या आगमन: 14 वर्ष का वनवास पूर्ण कर प्रभु राम, सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे। उनके स्वागत में अयोध्यावासियों ने दीप जलाए, जिसे आज हम दीपावली के रूप में मनाते हैं। राम का वनवास केवल एक सजा नहीं, बल्कि उनके आदर्श चरित्र, धर्म की स्थापना और राक्षसों के विनाश का माध्यम था इसतरह जब भी क़ोई संकट हो तो उससे कभी घबराना नहीं चाहिए ईश्वर को याद कीजिये सब ठीक होगा आखिर ऐ सब लीला भगवान ने इसलिए रची ताकि समय के अनुसार अपने को बदले और सुःख, दुःख, आपदा, विपत्ति इन सबसे विचलित नहीं होना चाहिए.कोरोना ऐसी आपदा नहीं कहना प्रधानमंत्री जी का जो भी इशारा हो लेकिन मेरे अनुसार ऐ एक महामारी नहीं आपदा है जो समय का चक्र है इससे परेशान ना हो।

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक रुख

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

-19 मई 2026 को सभी याचिकाएं खारिज- संविधान के अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या- जनसुरक्षा बनाम पशु अधिकार की बहस में नया मोड़ सुप्रीम कोर्ट द्वारा 19 मई 2026 को दिया गया निर्णय आने वाले समय में नगर निकायों, राज्य सरकारों, पशु कल्याण संगठनों और नागरिक समाज के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगा भारतीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा19 मई 2026 क़ा फैसला भारतीय न्यायिक इतिहास में केवल 'डॉग बाइट केस' नहीं बल्कि संविधान के अनुच्छेद 21की व्यापक व्याख्या सार्वजनिक सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन स्थापित करने वाले ऐतिहासिक निर्णय के रूप में याद किया जाएगा

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर भारत में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या, डॉग बाइट की घटनाओं, रेबीज संक्रमण और सार्वजनिक सुरक्षा को लेकर वर्षों से चल रही बहस को 19 मई 2026 को एक निर्णायक मोड़ तब मिला जब भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने डॉग लवर्स,पशु अधिकार कार्यकर्ताओं और विभिन्न गैर- सरकारी संगठनों द्वारा दायर उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिनमें नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। यह मामला केवल कुत्तों के पुनर्वास या नसबंदी तक सीमित नहीं था, बल्कि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत नागरिकों के भयमुक्त और सुरक्षित जीवन के अधिकार तथा पशु संरक्षण के बीच संतुलन की सबसे बड़ी संवैधानिक बहस बन गया। अदालत ने साफ कहा कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, रेलवे स्टेशनों, बस स्टैंडों, खेल परिसरों और अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी को सामान्य नहीं माना जा सकता। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सुरक्षा सर्वोपरि है तथा राज्य सरकारें केवल दर्शक बनकर नहीं रह सकतीं। इसी कारण सर्वोच्च अदालत ने नवंबर 2025 के आदेश में किसी भी प्रकार की ढील देने से इनकार करते हुएअपने फैसले को तीन भागों,पार्ट 1,पार्ट 2 और पार्ट 3 में विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया। साथियों मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि यह फैसला ऐसे समय आया है जब देश के अनेक राज्यों में डॉग बाइट के मामले भयावह स्तर तक पहुंच चुके हैं। अदालत के समक्ष रखे गए आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के श्रीगंगानगर में केवल 30 दिनों में 1084 डॉग बाइट के मामले सामने आए,जबकि तमिलनाडु में मात्र चार महीनों में दो लाख से अधिक डॉग बाइट के केस दर्ज किए गए। अदालत ने टिप्पणी की कि यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातस्थिति का संकेत है। न्यायालय ने कहा कि जब छोटे बच्चों के चेहरे नोचे जा रहे हों, बुजुर्गों पर झुंड बनाकर हमले हो रहे हों और अस्पतालों तक पहुंचने वाले मरीज रेबीज के भय में जी रहे हों, तब अदालत जमीनी वास्तविकताओं से आंखें नहीं मूंद सकती। यही कारण है कि इस फैसले को भारत में आवारा कुत्तों की नीति के इतिहास में एक ऐतिहासिक और निर्णायक निर्णय माना जा रहा है।

साथियों फैसले के पहले भाग में सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों, पशु जन्म नियंत्रण (एनिमल बर्थ कंट्रोल (एबीसी) रूल्स 2023 तथा भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा जारी दिशा-निर्देशों (एसओपी) की समीक्षा की। अदालत ने पाया कि अधिकांश राज्यों में नसबंदी, टीकाकरण, पुनर्वास और शेल्टर प्रबंधन की स्थिति बेहद कमजोर और असंगठित है। कई राज्यों में एंटी-रेबीज वैक्सीन की भारी कमी पाई गई, प्रशिक्षित पशु चिकित्सकों और तकनीकी स्टाफ का अभाव सामने आया तथा नगर निकायों के बीच समन्वय की कमी भी उजागर हुई।अदालत ने टिप्पणी की कि प्रशासनिक उदासीनता और नीतिगत विफलताओं के कारण ही डॉग बाइट की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। न्यायालय ने यह भी कहा कि यदि एनिमल बर्थ कंट्रोल नियमों का समय पर और प्रभावी तरीके से पालन किया गया होता, तो आज स्थिति इतनी भयावह नहीं बनती।

साथियों फैसले के दूसरे भाग में अदालत ने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ़ इंडिया (एडब्लूबीआई) द्वारा जारी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) और उससे जुड़े कानूनी ढांचे पर विस्तार से विचार किया। डॉग लवर्स और पशु अधिकार संगठनों की ओर से यह तर्क रखा गया कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी स्थान पर वापस छोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा न करने से क्षेत्रीय संघर्ष बढ़ सकते हैं तथा यह पशु क्रूरता की श्रेणी में आएगा। याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 तथा अनुच्छेद 51ए (ज़ी) का उल्लेख करते हुए कहा कि नागरिकों का यह मौलिक कर्तव्य है कि वे पशुओं के प्रति करुणा रखें। कुछ वकीलों ने 1960के पशु क्रूरता निवारण कानून तथा 1965 के पशु श्रम संबंधी प्रावधानों का भी हवाला दिया, जिनमें जानवरों के साथ अमानवीय व्यवहार को प्रतिबंधित किया गया है। फैसले के बाद एक्टिविस्टो ने प्रेस के समक्ष यह भी तर्क रखा गया कि देश में गौशालाओं की बदहाल स्थिति, सड़कों पर पशुओं की मृत्यु तथा बूचड़खानों की वास्तविकताओं पर भी समान संवेदनशीलता दिखाई जानी चाहिए।सर्वोच्च अदालत ने इन दलीलों को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। अदालत ने कहा कि पशु संरक्षण महत्वपूर्ण है, परंतु सार्वजनिक सुरक्षा उससे कम महत्वपूर्ण नहीं हो सकती। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि संविधान का अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं देता, बल्कि यह भयमुक्त और सम्मानजनक जीवन का अधिकार भी प्रदान करता है। यदि कोई बच्चा स्कूल जाते समय कुत्तों के झुंड के भय में जी रहा है, यदि बुजुर्ग पार्क या सड़क पर निकलने से डर रहे हैं, यदि अस्पतालों और बस स्टैंडों के आसपास लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, तो राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि वह नागरिकों की रक्षा करे। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता यह सिद्ध नहीं कर पाए कि एडब्लूबीआई की एसओपी संविधान या किसी कानून के विरुद्ध है। इसलिए सभी याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

साथियों फैसले के तीसरे भाग में सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक संस्थानों और संवेदनशील क्षेत्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए। अदालत ने आदेश दिया कि स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, खेल परिसरों, रेलवे स्टेशनों, बस डिपो, एयरपोर्ट तथा अन्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक क्षेत्रों से पकड़े गए आवारा कुत्तों को दोबारा उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा। उन्हें उचित शेल्टर होम्स या पुनर्वास केंद्रों में रखा जाएगा। अदालत ने राज्यों और स्थानीय निकायों को निर्देश दिया कि वे पर्याप्त संख्या में आधुनिक शेल्टर होम्स स्थापित करें, जहां कुत्तों के भोजन,चिकित्सा, नसबंदी और टीकाकरण की समुचित व्यवस्था हो। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि रेबीज संक्रमित या अत्यधिक आक्रामक व्यवहार वाले कुत्तों के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जा सकती है, जिसमें आवश्यक परिस्थितियों में एउथानसया अर्थात इच्छामृत्यु भी शामिल हो सकती है।सर्वोच्च अदालत की यह टिप्पणी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही कि 'लोगों की जान सबसे पहले है।' अदालत ने कहा कि पशु अधिकारों की रक्षा के नाम पर मानव जीवन और सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरे में नहीं डाला जा सकता। यह टिप्पणी इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में देशभर में डॉग फीडिंग और आवारा कुत्तों के संरक्षण को लेकर अनेक सामाजिक संघर्ष सामने आए हैं। कई स्थानों पर निवासी संघों और डॉग लवर्स के बीच विवाद अदालतों तक पहुंचे। कुछ मामलों में बच्चों और बुजुर्गों पर हमलों के बाद स्थानीय स्तर पर हिंसक प्रतिक्रियाएं भी देखी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले के माध्यम से यह स्पष्ट करने का प्रयास किया कि पशु संरक्षण और जनसुरक्षा के बीच संतुलन आवश्यक है, लेकिन सटीक प्राथमिकता नागरिकों के जीवन और सुरक्षा को दी जाएगी।

साथियों अदालत ने राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह निर्देश भी दिया कि वे नए एनिमल बर्थ कंट्रोल (एसओपी) केंद्र स्थापित करें तथा पर्याप्त मात्रा में एंटी-रेबीज वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करें न्यायालय ने कहा कि केवल कुत्तों को पकड़कर स्थानांतरित कर देना समाधान नहीं है। आवश्यक है कि वैज्ञानिक तरीके से नसबंदी, टीकाकरण, पुनर्वास और जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम चलाए जाएं। अदालत ने यह भी कहा कि नगर निकायों और राज्य सरकारों को डेटा आधारित नीति बनानी होगी, ताकि डॉग बाइट के मामलों, रेबीज संक्रमण और सार्वजनिक जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान कर समयबद्ध कार्रवाई की जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए कहा कि नवंबर 2025 के आदेश का सही ढंग से पालन नहीं किया गया। अदालत ने इसे अवमानना के रूप में देखने की चेतावनी दी और कहा कि यदि भविष्य में भी आदेशों की अनदेखी हुई तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक औरअवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही उच्च न्यायालयों को स्वतः संज्ञान यानी सु मोटो मामलों के माध्यम से निगरानी बनाए रखने का निर्देश दिया गया। यह निर्देश इस बात का संकेत है कि सर्वोच्च अदालत अब इस मुद्दे को केवल नगर निगमों का प्रशासनिक मामला नहीं बल्कि राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य और संवैधानिक अधिकारों कासटीक प्रश्न मान रही है।

साथियों इस पूरे विवाद में मेंनका गाँधी की प्रतिक्रिया भी चर्चा का विषय बनी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई नई बात नहीं है और नवंबर 2025 के आदेश का वास्तविक पालन करना लगभग असंभव है। उनके अनुसार यदि देशभर में आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर होम्स, चिकित्सा सुविधाएं और पुनर्वास केंद्र बनाने हों तो इसके लिए लगभग तीन लाख करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी, जो वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों में संभव नहीं दिखाई देता। उन्होंने यह भी कहा कि रेबीज संक्रमित या अत्यधिक बीमार कुत्तों को एउथानसया देने का प्रावधान पहले से ही कानून में मौजूद है,लेकिन उसकी प्रक्रिया जटिल और सख्त नियमों से नियंत्रित है। इसलिए व्यवहारिक स्तर पर इस आदेश को लागू करना आसान नहीं होगा।

साथियों, वास्तव में यही इस पूरे विवाद का सबसे बड़ा व्यावहारिक प्रश्न है। भारत में अनुमानित करोड़ों की संख्या में मौजूद आवारा कुत्तों के लिए पर्याप्त शेल्टर,पशु चिकित्सालय प्रशिक्षित स्टाफ और वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था करना एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। नगर निकाय पहले ही वित्तीय संकट, कचरा प्रबंधन,जल निकासी और शहरी अव्यवस्था जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। ऐसे में व्यापक स्तर पर डॉग शेल्टर प्रणाली खड़ी करना केवल न्यायिक आदेश से संभव नहीं होगा, बल्कि इसके लिए केंद्र और राज्यों के बीच समन्वित नीति, भारी बजटीय निवेश तथा दीर्घकालिक शहरी नियोजन की आवश्यकता होगी।इसके साथ ही यह फैसला भारत में पशु अधिकार आंदोलन के लिए भी एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जा रहा है। अब तक अदालतें सामान्यतः पशु संरक्षण के पक्ष में संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाती रही हैं, लेकिन इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने स्पष्ट किया कि पशु अधिकारों की व्याख्या मानव जीवन के अधिकार को कमजोर करके नहीं की जा सकती। अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 51ए (ज़ी) के अंतर्गत पशुओं के प्रति करुणा के नागरिक कर्तव्य को स्वीकार किया, लेकिन यह भी कहा कि यह कर्तव्य सार्वजनिक सुरक्षा और जनहित से ऊपर नहीं हो सकता।

साथियों अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखें तो अनेक देशों ने आवारा कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए अलग-अलग मॉडल अपनाए हैं। यूरोप के कई देशों में व्यापक शेल्टर प्रणाली, अनिवार्य पंजीकरण और पालतू पशुओं पर कठोर नियम लागू हैं। कुछ देशों में आक्रामक और संक्रमित कुत्तों के एउथानसया की स्पष्ट नीति है। वहीं कई एशियाई देशों में नसबंदी और टीकाकरण आधारित मॉडल अपनाया गया है। भारत की स्थिति इन दोनों के बीच फंसी हुई दिखाई देती है, जहां पशु अधिकार, धार्मिक-सांस्कृतिक संवेदनाएं, शहरी अव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा एक-दूसरे से टकराते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला इसी जटिल संतुलन को स्थापित करने का प्रयास माना जा सकता है।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क़ि यह निर्णय आने वाले समय में नगर निकायों,राज्य सरकारों, पशु कल्याण संगठनों और नागरिक समाज के लिए एक बड़ी परीक्षा साबित होगा। यदि अदालत के निर्देशों के अनुरूप आधुनिक शेल्टर होम्स, प्रभावी नसबंदी कार्यक्रम, व्यापक टीकाकरण और वैज्ञानिक पुनर्वास नीति विकसित नहीं की गई, तो यह फैसला केवल कागजों तक सीमित रह सकता है। दूसरी ओर यदि राज्यों ने इसे गंभीरता से लागू किया, तो संभव है कि भारत में पहली बार आवारा कुत्तों की समस्या को एक समन्वित सार्वजनिक स्वास्थ्य नीति के रूप में देखा जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतिम शब्दों में यह स्पष्ट कर दिया कि अदालत न तो पशुओं के खिलाफ है और न ही पशु प्रेमियों की भावनाओं को अस्वीकार करती है, लेकिन जब प्रश्न नागरिकों की जान, बच्चों की सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य का हो, तब राज्य की पहली जिम्मेदारी मनुष्यों के जीवन की रक्षा करना है।

कंक्रीट की चमक के बीच धुंधला पड़ता भविष्य

समाजशास्त्र हमें यह समझाता है कि किसी भी समाज की प्रगति केवल उसकी आर्थिक वृद्धि, ऊंची इमारतों या चमकदार शहरों से नहीं मापी जा सकती। किसी समाज का वास्तविक विकास इस बात से तय होता है कि वह अपने प्राकृतिक संसाधनों, पर्यावरण और मानवीय जीवन के साथ कैसा संबंध बनाता है। आज जब दुनिया बढ़ती गर्मी, अनियमित वर्षा और जल संकट का सामना कर रही है, तो यह केवल पर्यावरणीय समस्या नहीं है;

अजीत लाड़

यह सामाजिक संरचना और विकास की हमारी सोच का संकट भी है। दरअसल कुछ दशक पहले भारतीय समाज का प्रकृति से संबंध उपयोग का नहीं, सह-अस्तित्व का था। गांवों में पेड़ सिर्फ लकड़ी नहीं थे; वे सामाजिक जीवन का हिस्सा थे। तालाब केवल जल संग्रहण का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक संपर्क के केंद्र थे। लेकिन आधुनिक विकास मॉडल ने प्रकृति और समाज के इस संबंध को बदल दिया। जंगलों को 'भूमि संसाधन', नदियों को 'परियोजना' और पेड़ों को 'विकास में बाधा' मान लिया गया और यही वजह है कि भारत इस समय केवल बढ़ती गर्मी नहीं झेल रहा, बल्कि अपने विकास मॉडल की एक असहज सच्चाई से भी गुजर रहा है। सड़कों का जाल बिछ रहा है, शहर ऊपर की ओर फैल रहे हैं, इमारतें आसमान छू रही हैं और विकास के दावे लगातार ऊंचे होते जा रहे हैं। इसी शोर के बीच एक ऐसी खामोशी भी गहरी होती जा रही है। जिसमें पेड़ों के कटने की, सूखते जल स्रोतों की और बदलते मौसम की मार शामिल है।

यह प्रश्न अब केवल पर्यावरण का नहीं रह गया। यह समाज, जीवन और भविष्य का प्रश्न बन चुका है। एक समय था जब मौसम की अपनी एक लय होती थी। गर्मी अपने समय पर आती थी, बारिश का एक निश्चित क्रम होता था और सर्दियां अपनी पहचान रखती थीं। अब मौसम का व्यवहार अस्थिर दिखाई देता है। मार्च में मई जैसी तपन महसूस होती है, कई क्षेत्रों में सर्दियां छोटी हो रही हैं, कहीं कुछ घंटों की बारिश शहरों को जलमग्न कर देती है तो कहीं लंबे समय तक बादल बिना बरसे गुजर जाते हैं। प्रकृति का यह बदलता व्यवहार किसी रहस्यमय घटना का परिणाम नहीं, मानवीय गतिविधियों की लंबी श्रृंखला का प्रतिफल है। वैज्ञानिक आंकड़े इस चिंता को और स्पष्ट करते हैं। पृथ्वी का औसत तापमान औद्योगिक काल की तुलना में लगभग 1.2 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ चुका है। जलवायु विशेषज्ञों का मानना है कि तापमान में मामूली वृद्धि भी हीटवेव, सूखा, अतिवृष्टि और जल संकट जैसी घटनाओं को अधिक तीव्र बना देती है। भारत इस संकट के केंद्र में खड़ा दिखाई देता है। दुनिया की लगभग 18 प्रतिशत आबादी भारत में रहती है, जबकि वैश्विक मीठे जल संसाधनों का केवल लगभग 4 प्रतिशत हिस्सा देश के पास है। नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि लगभग 60 करोड़ भारतीय उच्च या अत्यधिक जल संकट की स्थिति का सामना कर रहे हैं। ऐसे में इन आंकड़ों के पीछे केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, एक सामाजिक कहानी भी छिपी हुई है।

विकास की वर्तमान अवधारणा ने शहरों को धीरे-धीरे कंक्रीट के जंगलों में बदल दिया। जहां कभी मिट्टी थी, वहां सीमेंट की परतें बिछ गईं। जहां पेड़ों की छांव होती थी, वहां पार्किंग और बहुमंजिला ढांचे खड़े हो गए। जहां तालाब थे, वहां कॉलोनियां बस गईं। इतना ही नहीं शहरों का बदलता स्वरूप भी इस संकट का बड़ा कारण है। पिछले कुछ दशकों में शहरों का विस्तार हुआ, लेकिन उसके साथ हरियाली नहीं बढ़ी। पेड़ों की जगह पार्किंग आई, तालाबों की जगह कॉलोनियां बनीं और मिट्टी की जगह सीमेंट बिछा दिया गया। आज शहर 'कंक्रीट के जंगल' बनते जा रहे हैं। वैज्ञानिक इसे अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं, जिसमें कंक्रीट और डामर दिनभर गर्मी सोखते हैं और रात में छोड़ते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि शहरों का तापमान आसपास के क्षेत्रों से अधिक हो जाता है। जर्मन समाजशास्त्री उलरिच बेक ने अपनी 'जोखिम समाज' अवधारणा में चेताया था कि आधुनिक विकास केवल सुविधाएं नहीं लाता, वह ऐसे जोखिम भी पैदा करता है जो धीरे-धीरे पूरी मानव सभ्यता को प्रभावित करने लगते हैं। जलवायु परिवर्तन आज उसी चेतावनी की सबसे स्पष्ट तस्वीर बनकर सामने खड़ा है।

अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव केवल मौसम तक सीमित नहीं है। इसका असर सीधे मनुष्य के शरीर, स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन पर पड़ रहा है। बढ़ती गर्मी के साथ हीट स्ट्रोक, श्वसन संबंधी बीमारियां और जल संकट जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। सबसे अधिक प्रभावित वह वर्ग हो रहा है जो खुले आसमान के नीचे जीवन और श्रम करता है। एक वातानुकूलित कार्यालय में बैठा व्यक्ति और सड़क निर्माण स्थल पर काम करने वाला मजदूर एक जैसी गर्मी का अनुभव नहीं करते। एक परिवार पानी खरीद सकता है, दूसरा परिवार पानी के एक टैंकर का इंतजार करता है।

पर्यावरणीय संकट का बोझ समान रूप से वितरित नहीं होता। उसका सबसे भारी भार अक्सर उन कंधों पर आता है जिन्होंने इस संकट को पैदा करने में सबसे कम योगदान दिया होता है। समस्या विकास में नहीं है। समस्या उस सोच में है जिसने विकास और प्रकृति को दो अलग दिशाओं में खड़ा कर दिया। पेड़ विकास के विरोधी नहीं हैं। जल स्रोत बाधा नहीं हैं। जंगल खाली जमीन नहीं हैं। सभ्य समाज की पहचान केवल उसकी आर्थिक गति से नहीं होती। उसकी पहचान इस बात से होती है कि उसने अपनी अगली पीढ़ी के लिए कैसी दुनिया छोड़ी। यदि विकास का अर्थ केवल कंक्रीट की ऊंचाई रह गया और सांस लेने योग्य हवा पीछे छूट गई, तो आने वाला समय हमारी उपलब्धियों का नहीं, हमारी दूरदर्शिता की कमी का दस्तावेज बनेगा। इतिहास उन सभ्यताओं को अधिक देर तक याद रखता है जिन्होंने निर्माण के साथ संरक्षण को भी महत्व दिया, जिन्होंने भविष्य की कीमत पर वर्तमान का उत्सव नहीं मनाया।

(स्वतंत्र लेखक एवं पत्रकार)

(यह लेखक के व्यक्तिगत विचार हैं इससे संपादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं है)

बिलासपुर में बिजली संकट गहराया, सप्लाई ठप होने से पानी की किल्लत

नाराज लोगों ने बिजली ऑफिस का घेराव किया

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। भीषण गर्मी के बीच बिलासपुर शहर में लगातार बिगड़ती बिजली व्यवस्था को लेकर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा घंटों बिजली कटौती, लो वोल्टेज और ट्रांसफार्मर खराब होने की घटनाओं से परेशान नागरिकों ने गुरुवार को नेहरू नगर स्थित बिजली कार्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा शहर के मंगला क्षेत्र, भक्त कंवरराम नगर, कस्तूरबा नगर और सिंधी कॉलोनी में पिछले कई दिनों से बिजली आपूर्ति लगातार बाधित हो रही है स्थानीय लोगों का आरोप है कि विभाग बिना सूचना के बिजली कटौती कर रहा है जिससे आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है बुधवार रात भी कई इलाकों में घंटों बिजली गुल रही और गुरुवार सुबह तक सप्लाई पूरी तरह सामान्य नहीं हो सकी बिजली बंद रहने का असर पानी सप्लाई पर भी पड़ा। लोगों ने बताया कि मोटर और पंप नहीं चलने के कारण पीने के पानी की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है भीषण गर्मी में लोगों को रातभर अंधेरे में समय बिताना पड़ा जिससे बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी हुई गुरुवार सुबह हालात उस समय और बिगड़ गए जब सिंधी कॉलोनी स्थित एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई स्थानीय रहवासियों ने आरोप लगाया कि ट्रांसफार्मर लंबे समय से खराब स्थिति में था, लेकिन विभाग ने समय रहते उसकी मरम्मत या बदलाव नहीं किया लोगों का कहना है कि लगातार लो वोल्टेज के कारण घरों के बिजली उपकरण, कूलर, पंखे और पानी की मोटर भी खराब हो रही हैं। समस्या से नाराज बड़ी संख्या में वार्डवासी गुरुवार सुबह नेहरू नगर स्थित बिजली कार्यालय पहुंचे प्रदर्शनकारियों ने विभाग के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कार्यालय का घेराव किया कुछ प्रदर्शनकारी कार्यालय के अंदर तक पहुंच गए और अधिकारियों से तत्काल समाधान की मांग की प्रदर्शनकारियों ने कहा कि यदि जल्द नया ट्रांसफार्मर नहीं लगाया गया और नियमित बिजली सप्लाई बहाल नहीं हुई तो वे सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे लोगों का आरोप है कि बार-बार शिकायत करने के बावजूद विभाग केवल आश्वासन दे रहा है लेकिन स्थायी समाधान नहीं किया जा रहा वहीं बिजली विभाग के कार्यपालन अभियंता ने लोगों को भरोसा दिलाया कि खराब ट्रांसफार्मर को जल्द बदला जाएगा और प्रभावित इलाकों में बिजली व्यवस्था सामान्य करने के लिए तकनीकी टीम लगातार काम कर रही है विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि भीषण गर्मी और बढ़ते लोड के कारण कई क्षेत्रों में ट्रांसफार्मर और लाइनें प्रभावित हो रही हैं फिलहाल नागरिकों को उम्मीद है कि प्रशासन और बिजली विभाग जल्द राहत देंगे ताकि गर्मी के मौसम में उन्हें बिजली और पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के संकट से निजात मिल सके।

बच्चों संग महिला का माधव चौक पर प्रदर्शन

खुद पर पेट्रोल छिड़ककर बैठी, भीम आर्मी नेता पर मारपीट-छेड़छाड़ का आरोप लगाया

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी के माधव चौक पर गुरुवार दोपहर एक महिला ने अपने तीन बच्चों के साथ खुद पर पेट्रोल छिड़ककर धरना प्रदर्शन किया। महिला ने भीम आर्मी नेता ठाकुरलाल जाटव और उसके साथियों पर मारपीट व छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए। सूचना मिलने पर देहात थाना पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को कार्रवाई का आश्वासन देकर थाने ले गई। देहात थाना क्षेत्र के रायश्री गांव की निवासी महिला ने बताया कि उसके पति ने उसे छोड़कर दूसरी महिला के साथ रहना शुरू कर दिया है। महिला का आरोप है कि उसके ममिया ससुर ठाकुरलाल जाटव, सास और देवर ने मिलकर यह सब करवाया। इसके बाद वह अपने बच्चों के साथ सरकारी जमीन पर बने कच्चे मकान में रहने को मजबूर हो गई।

जमीन बिकवाने का आरोप लगाया: महिला ने यह भी आरोप लगाया कि ठाकुरलाल जाटव ने परिवार की जमीन बिकवा दी, लेकिन उसे उसका हिस्सा नहीं दिया। वह लंबे समय से अपने हिस्से की मांग कर रही है, लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो रही। महिला ने चिंता व्यक्त की कि वह जिस सरकारी जमीन पर रह रही है, प्रशासन उसे कभी भी खाली करा सकता है, जिससे उसके बच्चों के साथ रहने का संकट खड़ा हो जाएगा। महिला के अनुसार, इसी विवाद के चलते ठाकुरलाल जाटव और उसके साथियों ने उसके साथ मारपीट की और उसकी बेटी के साथ छेड़छाड़ भी की। उसने बताया कि इस मामले की शिकायत पहले भी थाने और एसपी कार्यालय में की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई न होने से परेशान होकर महिला ने गुरुवार को बच्चों के साथ माधव चौक पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर भीम आर्मी नेता ठाकुरलाल जाटव ने महिला के आरोपों को निराधार बताया है। उनका कहना है कि महिला का बेटा उनके भांजे की दुकान का ताला तोड़कर चोरी का प्रयास करते हुए पकड़ा गया था। इसी मामले में कार्रवाई से बचने के लिए महिला झूठे आरोप लगा रही है। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच लंबे समय से जमीन और संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा है। बता दें कि महिला के परिवार पर पहले भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। उनके अनुसार महिला की बड़ी बहन ने अपने पति की हत्या प्रेमी और बेटों के साथ मिलकर कराई थी, जिसमें इस महिला पर भी साजिश में शामिल होने के आरोप लगे थे।

पुलिस बोली- जांच के बाद कार्रवाई करेंगे: इधर देहात थाना प्रभारी विकास यादव का कहना है कि मामला पारिवारिक संपत्ति विवाद से जुड़ा हुआ है। गांव में दुकान के आधिपत्य को लेकर दोनों पक्षों के बीच विवाद हुआ था। महिला द्वारा छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए हैं। पुलिस मौके का मुआयना कर रही है और साक्षियों के बयान लेने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

शिवपुरी में भजन समिति सदस्य पर एफआईआर

महिला से अश्लीलता और धमकी, बेटे की नौकरी और पति के क्लिनिक को बनाया निशाना

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। शिवपुरी शहर में भजन समिति से जुड़े एक युवक पर महिला के साथ अश्लील हरकत करने और ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है आरोपी संजय गौतम पर पीड़िता को मिलने का दबाव डालने, अश्लील बातें करने और विरोध करने पर उसके परिवार को आर्थिक व मानसिक परेशानियों में डालने का आरोप है फतेहपुर क्षेत्र की 40 वर्षीय महिला ने पुलिस को बताया कि वह करीब पांच महीने पहले बागेश्वर हनुमान चालीसा भजन समिति से जुड़ी थी इसी दौरान उसकी पहचान आरोपी संजय गौतम से हुई बाद में संजय ने अपनी अलग समिति बनाई और महिला को उसमें जोड़ लिया महिला का आरोप है कि समिति के कार्यक्रमों के दौरान संजय ने उसके साथ अशोभनीय हरकत की 28 जनवरी 2026 के हनुमान चालीसा कार्यक्रम में भी ऐसा ही व्यवहार देखने को मिला महिला ने आगे बताया कि उसने जब आरोपी की अनुचित मांगें न मानने का निर्णय लिया तो उसने रंजिश के चलते उसके बेटे की नौकरी छुड़वा दी इसके अलावा तीन दिन पहले आरोपी ने महिला के पति का खरई-तेंदुआ स्थित क्लिनिक भी बंद करा दिया आरोपी ने महिला को फोन पर धमकी देते हुए कहा जब तक तुम मुझसे नहीं मिलोगी तुम्हारा पति काम नहीं कर पाएगा यदि मिलोगी तो बेटे की नौकरी लगवा दूंगा पीड़िता ने पुलिस को इस बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग भी सौंपी है 20 मई को भी आरोपी ने अश्लील मांग की और बेटे की नौकरी का लालच दिया। कोतवाली पुलिस ने आरोपी संजय गौतम के खिलाफ शिकायत और कॉल रिकॉर्डिंग के आधार पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए कानूनी कार्रवाई जल्द ही पूरी की जाएगी और आरोपी को जिम्मेदार ठहराया जाएगा।

बंद किराना दुकान में आग, गश्त कर रही पुलिस ने देखीं लपटें

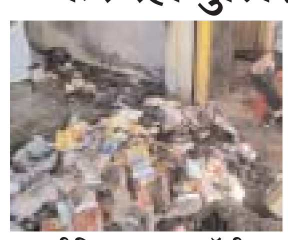

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले के लुकवासा कस्बे में स्टेशन रोड स्थित एक किराना दुकान में बुधवार देर रात अचानक आग लग गई। इस घटना में दुकान के अंदर रखा करीब डेढ़ लाख रुपए का सामान जलकर राख हो गया। रात में गश्त कर रही पुलिस टीम ने शटर से लपटें उठती देख दुकानदार को सूचना दी और करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। दुकान संचालक पंकज गुप्ता ने बताया कि उन्होंने बुधवार रात करीब 10:30 बजे अपनी दुकान बंद की थी। इसके बाद रात लगभग 12 बजे गश्त पर निकली पुलिस टीम ने बंद दुकान से आग की लपटें उठती देखीं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल दुकानदार को घटना की सूचना देकर मौके पर बुलाया।

पड़ोसी के बोरवेल से बुझाई आग: दुकानदार के मौके पर पहुंचने के बाद शटर का ताला तोड़ा गया। इसके बाद पड़ोस में लगे बोरवेल को चालू कर पानी से आग बुझाने का प्रयास शुरू किया गया। मौके पर मौजूद लोगों और पुलिस की मदद से करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया।

शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका: फिलहाल आग लगने के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका है। हालांकि, प्रारंभिक जांच के आधार पर शॉर्ट सर्किट को आग लगने का संभावित कारण माना जा रहा है। इस घटना में दुकान का लगभग सारा किराना सामान जलकर नष्ट हो गया है, जिससे व्यापारी को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है।

कांग्रेस में पार्टी छोड़ने वाले को जिलाध्यक्ष का कमान

मनोज साहू को बनाया ओबीसी प्रकोष्ठ का अध्यक्ष, 2023 में दिया था इस्तीफा

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। मनेंद्रगढ़ में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की संगठनात्मक नियुक्तियों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान कांग्रेस छोड़कर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी (गोंगपा) में शामिल हुए मनोज कुमार साहू को कांग्रेस ने ओबीसी प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। मनोज कुमार साहू पहले ब्लॉक कांग्रेस कमेटी खड़गवां के अध्यक्ष रह चुके हैं। अक्टूबर 2023 में मनेंद्रगढ़ विधानसभा सीट से तत्कालीन विधायक डॉ. विनय जायसवाल का टिकट कटने के बाद उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। 21 अक्टूबर 2023 को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज को पत्र लिखकर उन्होंने पार्टी नेतृत्व पर उपेक्षा का आरोप लगाया था।

कांग्रेस से निष्कासन और संगठनात्मक कार्रवाई: इस्तीफे के अगले दिन 22 अक्टूबर 2023 को जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने आदेश जारी कर मनोज साहू को पद से हटा दिया था। आदेश में सूर्य प्रकाश उइके को खड़गवां ब्लॉक का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इसमें स्पष्ट उल्लेख था कि मनोज साहू गोंडवाना गणतंत्र पार्टी में शामिल हो चुके हैं।

गोंगपा में शामिल होने का राजनीतिक घटनाक्रम: राजनीतिक हलकों में चर्चा रही कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पाली-तानाखार विधायक तुलेश्वर हीरा सिंह मरकाम ने मनोज कुमार साहू को पार्टी का गमछा पहनाकर सदस्यता दिलाई थी। विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ सक्रिय भूमिका निभाई थी।

कांग्रेस की नई नियुक्ति पर सवाल: पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिस नेता ने चुनाव के समय पार्टी छोड़ दी थी, उसे औपचारिक वापसी के बिना इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना समझ से परे है।

समर्थन मूल्य भुगतान में बड़ा साइबर घोटाला: किसानों की मेहनत की कमाई फर्जी खातों में ट्रांसफर, 100 खाते फ्रीज

मीडिया ऑडीटर, शिवपुरी (निप्र)। जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने वाले किसानों के भुगतान में बड़े साइबर फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है किसानों द्वारा दिए गए बैंक खातों के बजाय उनकी राशि फर्जी खातों में ट्रांसफर कर दी गई इस घटना ने सरकारी भुगतान प्रणाली, आधार लिंकिंग व्यवस्था और बैंकिंग सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं साइबर सेल ने जांच के दौरान करीब 100 संदिग्ध खातों को फ्रीज कर कार्रवाई शुरू कर दी है जानकारी के अनुसार कोलारस, बदरवास और शिवपुरी ब्लॉक की विभिन्न सहकारी समितियों से जुड़े मामलों की जांच जारी है किसानों ने भुगतान के लिए एसबीआई, एक्सिस बैंक और कॉपरेटिव बैंक खातों की जानकारी दी थी लेकिन लाखों रुपए फिनो बैंक के संदिग्ध खातों में पहुंच गए साइबर सेल प्रभारी धर्मेंद्र सिंह जाट ने बताया कि शुरुआती तौर पर दो किसानों की शिकायत दर्ज हुई थी जिसके बाद जांच का दायरा बढ़ाया गया। जांच में सामने आया कि गुना जिले के चक्का क्षेत्र में रामलाल सहरिया के नाम से जारी कियोस्क आईडी का उपयोग कर संदिग्ध खाते खोले गए इन खातों को किसानों के आधार नंबर से लिंक कर सरकारी भुगतान डायवर्ट किया गया ग्राम गंगौरा के किसान भजनसिंह ने पत्नी सुशीला देवी के नाम से 86 क्विंटल गेहूं बेचा था करीब 2.25 लाख रुपए एक्सिस बैंक खाते में आने थे लेकिन रकम फर्जी फिनो बैंक खाते में पहुंच गई वहीं बेंहटा गांव के किसान विश्वीर सिंह जाट के 6.65 लाख रुपए भी संदिग्ध खाते में ट्रांसफर हो गए इसी तरह सूखा राजापुर निवासी अमरसिंह लोधी के 1.48 लाख रुपए और सुरवाया निवासी राजेंद्र उर्फ गब्बर सिंह गुर्जर के 44 हजार 626 रुपए भी फर्जी खातों में पहुंच गए हालांकि समय रहते खाते होल्ड होने से कुछ रकम बचा ली गई। जांच एजेंसियों के अनुसार ठगों ने बिना दस्तावेज और बिना बायोमेट्रिक सत्यापन के किसानों के नाम पर खाते खोले बाद में इन्हें आधार से लिंक कर दिया गया एनपीसीआई सिस्टम में नया आधार लिंक खाता जुड़ते ही सरकारी भुगतान उसी खाते में ट्रांसफर होने लगा जिसका फायदा साइबर अपराधियों ने उठाया विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो पीएम आवास योजना, लाड़ली बहना योजना, वृद्धावस्था पेंशन और अन्य सरकारी योजनाओं के भुगतान भी इसी तरह प्रभावित हो सकते हैं पुलिस और साइबर सेल पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है।

तपती गर्मी में राहत की बूंदें: थोरगी गांव में हैंडपंप सुधार से ग्रामीणों को मिली बड़ी राहत

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते जल संकट के बीच मनेंद्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर (एमसीबी) जिले के ग्रामीण इलाकों में पेयजल व्यवस्था बनाए रखने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है विकासखंड भरतपुर के ग्राम थोरगी में विभागीय टीम ने खराब पड़े हैंडपंपों की मरम्मत, निरीक्षण और सुधार कार्य कर ग्रामीणों को बड़ी राहत पहुंचाई है तेज गर्मी के कारण जिले के कई गांवों में जलसंकट गहराने लगा है ऐसे में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने खराब और बंद पड़े हैंडपंपों को प्राथमिकता के आधार पर सुधारने का अभियान शुरू किया है इसी क्रम में थोरगी गांव में लंबे समय से खराब पड़े हैंडपंपों की शिकायत मिलने पर विभागीय टीम मौके पर पहुंची और तत्काल मरम्मत कार्य शुरू किया तकनीकी कर्मचारियों ने हैंडपंपों की जांच कर आवश्यक सुधार किए, जिसके बाद जल आपूर्ति फिर से सुचारु हो गई हैंडपंपों के चालू होने के बाद गांव के लोगों ने राहत की सांस ली ग्रामीणों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से गांव में पेयजल की गंभीर समस्या बनी हुई थी भीषण गर्मी के कारण कुएं और अन्य जल स्त्रोत भी प्रभावित हो रहे थे जिससे लोगों को दूर-दराज के इलाकों से पानी लाना पड़ रहा था खासकर महिलाओं और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

ग्रामीणों ने बताया कि समय पर विभाग द्वारा की गई मरम्मत से अब गांव में पेयजल संकट काफी हद तक कम हो गया है। लोगों ने प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि गर्मी के इस कठिन समय में त्वरित कार्रवाई से आमजन को बड़ी राहत मिली है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के अधिकारियों ने बताया कि जिलेभर में लगातार पेयजल स्त्रोतों की निगरानी की जा रही है। विभागीय अमला गांव-गांव पहुंचकर हैंडपंपों और अन्य जल स्त्रोतों का निरीक्षण कर रहा है ताकि कहीं भी पेयजल संकट की स्थिति न बने। अधिकारियों के अनुसार, खराब हैंडपंपों की सूची तैयार कर प्राथमिकता के आधार पर सुधार कार्य किए जा रहे हैं।

मौत-लूट मामला, आरोपी को बचा रही पुलिस; शिकायत लेकर एसपी के पास पहुंचे महिला के परिजन

शिवपुरी (निप्र)। जिले के खनियाधाना थाना क्षेत्र में एक महिला की मौत से जुड़े लूटकांड मामले में पीड़ित परिवार गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंचा। परिजनों ने पुलिस पर आरोपी को बचाने का आरोप लगाते हुए ज्ञापन सौंपा और कहा कि आरोपी का नाम बताने के बाद भी पुलिस उसे गिरफ्तार नहीं कर रही है। पीड़ित रामनिवास लोधी ने बताया कि यह घटना 1 मई 2026 की रात की है। वह अपनी रिश्तेदार मीना लोधी के साथ बाइक से एक शादी समारोह से लौट रहे थे। अछरौनी गांव के पास नहर पुलिया से पहले एक बाइक पर सवार तीन युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उन्हें रोका।

शिक्षक भर्ती में आरक्षण नियमों की अनदेखी पर हाईकोर्ट सख्त

OBC कोटे में तय सीमा से अधिक दिव्यांग नियुक्तियां गलत, 90 दिन में नई मेरिट लिस्ट बनाने के आदेश

मीडिया ऑडीटर, बिलासपुर (निप्र)। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने राज्य की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नियमों के उल्लंघन को लेकर राज्य सरकार और चयन समिति पर सख्त टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पदों पर तय सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों की नियुक्ति केवल मेरिट के आधार पर करना कानून और आरक्षण व्यवस्था दोनों के खिलाफ है कोर्ट ने भर्ती प्रक्रिया को त्रुटिपूर्ण बताते हुए 90 दिनों के भीतर नई मेरिट लिस्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं यह फैसला जस्टिस राकेश मोहन पांडेय की एकलपीठ ने उमेश कुमार श्रीवास, नेहा साहू, प्रमोद कुमार साहू समेत अन्य अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद दिया याचिकाकर्ताओं ने लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा 9 मार्च 2019 को जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन में चयन प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे याचिका में बताया गया कि व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक पदों की भर्ती में ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों ने भी मेरिट सूची में स्थान प्राप्त किया था लेकिन अंतिम चयन सूची जारी होने पर ओबीसी कोटे के भीतर तय 7 प्रतिशत सीमा से अधिक दिव्यांग उम्मीदवारों को शामिल कर लिया गया इससे सामान्य ओबीसी अभ्यर्थियों के अवसर प्रभावित हुए मामले में व्याख्याता बायोलॉजी ई-संवर्ग के 200 पदों का उदाहरण दिया गया जिसमें ओबीसी वर्ग के हिस्से में आने वाले पदों में से केवल 14 पद दिव्यांग आरक्षण के लिए निर्धारित थे आरोप है कि चयन समिति ने छह अतिरिक्त दिव्यांग उम्मीदवारों को मेरिट के आधार पर सीधे ओबीसी कोटे में समायोजित कर दिया इसी प्रकार की प्रक्रिया शिक्षक गणित और सहायक शिक्षक विज्ञान भर्ती में भी अपनाई गई राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि चयनित दिव्यांग उम्मीदवारों ने उच्च मेरिट प्राप्त की थी इसलिए उन्हें अवसर दिया गया सरकार ने कहा कि संबंधित सर्कुलर के अनुसार योग्यता के आधार पर नियुक्ति की गई। हालांकि याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक इंदिरा साहनी फैसले का हवाला देते हुए कहा कि चयन समिति की प्रक्रिया आरक्षण नियमों और संवैधानिक व्यवस्था के विपरीत है सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि सामाजिक आरक्षण और विशेष आरक्षण की प्रकृति अलग-अलग होती है।

भालू हमले की पीड़िता के घर पहुंचेगा मेडिकल बोर्ड

एमसीबी जिला प्रशासन सोशल मीडिया में पोस्ट के बाद जागा, दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाने आदेश जारी

मीडिया ऑडीटर, एमसीबी (निप्र)। जिले के जनकपुर क्षेत्र के ग्राम चिडोला निवासी प्रेमबाई गोंड को अब दिव्यांग प्रमाण पत्र बनवाने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सोशल मीडिया पर उनकी परेशानी सामने आने के बाद जिला मेडिकल बोर्ड उनके घर पहुंचकर स्वास्थ्य परीक्षण करेगा और आवश्यक प्रक्रिया पूरी करेगा। प्रेमबाई पर 20 जून 2025 को भालू ने हमला किया था, जिसमें उनके सिर में गंभीर चोट आई थी और उनकी एक आंख पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। इस घटना के बाद वन विभाग की ओर से उन्हें सहायता राशि और बीमा का लाभ मिलना था, जिसके लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य बताया गया था।

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने पर जागा प्रशासन: प्रेमबाई गोंड बीते कई महीनों में छह बार मनेंद्रगढ़ मेडिकल बोर्ड के कार्यालय जा चुकी थीं, लेकिन उनका दिव्यांग प्रमाण पत्र नहीं बन पाया था। उनकी इस परेशानी को लेकर एक व्यक्ति ने उनका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया था।

1 साल बाद भी गांव ठीक नहीं हुआ है: वीडियो में बताया गया था कि घटना को लगभग एक वर्ष होने जा रहा है, लेकिन महिला का घाव अब तक पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है और वह लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।

जिला मेडिकल बोर्ड की टीम अब पहुंचेगी पीड़िता के घर: मामले का संज्ञान लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. अविनाश खरे ने निर्णय लिया कि पीड़ित महिला को अब अस्पतालों और दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इसके बजाय, जिला मेडिकल बोर्ड स्वयं उनके घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करेगा और प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया पूरी करेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जरूरतमंद, असहाय और विशेष परिस्थितियों में रहे लोगों तक सेवाएं पहुंचाना शासन की प्राथमिकता है। प्रशासन का उद्देश्य केवल योजनाएं संचालित करना नहीं, बल्कि हर जरूरतमंद व्यक्ति तक सहायता पहुंचाना है।

आमने-सामने से टकराईं यात्री बस, कांच फूटे रायसेन में संकरा मोड होने पर टकराईं; स्टेट हाईवे पर हादसा

मीडिया ऑडीटर, रायसेन (निप्र)। रायसेन जिले के सिलवानी-गैरतगंज स्टेट हाईवे-44 पर बुधवार दोपहर दो यात्री बसों की आमने-सामने टक्कर हो गई। यह घटना जूनिया पुल के पास एक मोड़ पर हुई। हादसे में दोनों बसों के आगे के कांच टूट गए, हालांकि किसी भी यात्री को गंभीर चोट नहीं आई। मिली जानकारी के अनुसार, शक्ति बस सिलवानी से गैरतगंज की ओर जा रही थी, जबकि शुभम बस गैरतगंज से सिलवानी की तरफ आ रही थी। जूनिया पुल के पास संकरे मोड़ पर क्रॉसिंग के दौरान दोनों बसें आपस में टकरा गईं। इस टक्कर में दोनों बसों में सवार सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया था। सड़क पर यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से सामान्य किया गया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, मोड़ संकरा होने और बसों की तेज रफ्तार के कारण यह हादसा हुआ। घटना के तुरंत बाद दोनों बसों के चालक और परिचालकों ने सभी यात्रियों को सुरक्षित बसों से बाहर निकाला।

जमीनी विवाद में किसान के खेत में लगाई आग सीहोर में हजारों का सामान जलकर राख

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। सीहोर जिले के हीरापुर गांव में एक किसान के खेत में आग लगाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि यह आग आपसी रंजिश के चलते लगाई गई, जिसमें किसान का हजारों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया। इस घटना के बाद पीड़ित परिवार को आर्थिक नुकसान हुआ है। यह घटना हीरापुर निवासी किसान कमलेश परमार के खेत में हुई। कमलेश के भाई प्रेम नारायण परमार ने अपने पड़ोसी पर आग लगाने का आरोप लगाया है। प्रेम नारायण के अनुसार, पड़ोसी से उनका पुराना जमीनी विवाद चल रहा था, जिसके चलते रंजिश में यह आग लगाई गई।

किसान को हजारों रुपए का नुकसान हुआ : गर्मी और तेज हवाओं के कारण आग तेजी से पूरे खेत में फैल गई। इस अग्निकांड में किसान कमलेश परमार को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। खेत में रखी सूखी लकड़ियां, गोबर के कंडे, फसलों के लिए रखा खाद और खेती में उपयोग होने वाले कृषि उपकरण सहित हजारों रुपए का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। पीड़ित किसान के अनुसार, यह उनके सालभर की मेहनत की कमाई का नुकसान है। ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया और तत्काल फायर ब्रिगेड को सूचना दी। हालांकि, सूचना देने के एक घंटे बाद भी दमकल विभाग की गाड़ी मौके पर नहीं पहुंची। ग्रामीणों का कहना है कि यदि फायर ब्रिगेड समय पर पहुंच जाती, तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था।

पुलिस ने कहा- पहले होगी नुकसान की जांच : आग बुझने के बाद पीड़ित परिवार न्याय की आस में थाने पहुंचा और आरोपी पड़ोसी के खिलाफ नामजद आवेदन देकर मामला दर्ज करने की मांग की। लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाने के बजाय मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। पुलिस का कहना है कि पहले पटवारी की रिपोर्ट आएगी, नुकसान का आकलन होगा, उसके बाद ही मामला दर्ज किया जाएगा।

कूप रिचार्ज पिट बनाने की विधि

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। कृषि विभाग ने बताया कि कूप रिचार्ज पिट बनाने के लिए एक खास संरचना तैयार की गई है। जिसमें पत्थर और मोटी रेत की परतें होंगी। पिट का निर्माण कुएं से 3 से 6 मीटर की दूरी पर किया जाएगा। इसके लिए 3 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा और 8 मीटर गहर गड्ढ़ा खोदा जा रहा है। गड्ढ़े में 8 इंच का पाइप डालकर इसे कुएं के अंदर डाला जाएगा। फिर कुएं में पाइप के छोर पर एल्बो लगाकर 1 फिट का पाइप नीचे की तरफ लगाया जाएगा। इसके बाद पाइपलाइन के जरिए कुएं तक पहुंचाया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। यह अभियान 30 जून तक जारी रहेगा। अभियान में बारिश के पानी को सहेजने व पुराने जल स्त्रोतों का जीर्णोद्धार करने का कार्य किया जा रहा है। तीन माह तक चलने वाले इस अभियान के तहत पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बारिश के पानी का संयचन करने व पुराने जल स्त्रोतों को नया जीवन देने के लिए सभी जिलों में खेत-तालाब, कूप रिचार्ज पिट, चैक, डैम, अमृत सरोवर सहित अन्य कार्य किए जा रहे हैं।

जनगणना 2027 के प्रथम चरण के डाटा की गुणवत्ता जांच के निर्देश जारी

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। जनगणना संचालन निदेशालय द्वारा जनगणना 2027 के प्रथम चरण के अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के डाटा की गुणवत्ता जांच को लेकर निर्देश जारी किए गए हैं। प्रदेश में यह कार्य 01 मई से 30 मई 2026 तक संचालित किया जा रहा है। जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि छूटे हुए भवन, मकान एवं परिवारों को पुनः विजिट कर शामिल किया जाए तथा फील्ड वर्क की गुणवत्ता की जांच कर आवश्यक सुधार सुनिश्चित किए जाएं। सभी प्रगणकों को प्रत्येक परिवार से 'स्व-जनगणना' संबंधी जानकारी की पुष्टि करने, सभी प्रश्न पूछने और किसी भी प्रश्न को स्किप नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही पर्यवेक्षकों को प्रगणकों द्वारा एकत्रित डाटा की जांच कर त्रुटियों में सुधार कराने, चयनित एचएलबी में फील्ड निरीक्षण करने तथा सीएमएमएस पोर्टल के माध्यम से गुणवत्ता परीक्षण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। लॉक्ड हाउस की स्थिति में कम से कम तीन बार विजिट कर जानकारी दर्ज करने के लिए भी कहा गया है।

सागर में ट्रक ने बाइक सवार 2 छात्रों को कुचला कॉलेज जा रहे थे, मौके पर मौत

गुस्साए लोगों ने हाईवे पर चक्काजाम किया

मीडिया ऑडीटर, सागर (निप्र)। सागर के कैंट थाना क्षेत्र में बुधवार को नेशनल हाईवे-44 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में कॉलेज जा रहे बाइक सवार दो छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर चक्काजाम कर दिया। पुलिस और प्रशासन की टीम ने मौके पर पहुंचकर लोगों को शांत कराया और ट्रक को जब्त कर लिया है। मृतकों की पहचान संजय (20) पिता महेश रजक निवासी सेमरा हार्ट और नितिन (20) पिता लखन अहिरवार निवासी कोलुआ के रूप में हुई है। दोनों छात्र बीएससी प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहे थे। जानकारी के अनुसार, बुधवार को दोनों एक ही बाइक पर सवार होकर अपने गांव से कॉलेज के लिए सागर आ रहे थे, तभी रानीपुरा के पास यह हादसा हो गया। घटना करीब साढ़े 12 बजे के आसपास की है।

ट्रक के पहिए की चपेट में आने से गई जान : रानीपुरा के पास नेशनल हाईवे पर पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार ट्रक ने छात्रों की बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण दोनों छात्र अनियंत्रित होकर सड़क पर जा गिरे। इसी दौरान वे ट्रक के पहिए की चपेट में आ गए, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने हाईवे पर किया चक्काजा हादसे के तुरंत बाद मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने घटना के विरोध में हाईवे पर चक्काजाम कर दिया, जिससे करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलने पर कैंट थाना प्रभारी और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले में सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोगों ने चक्काजाम खोला।

ट्रक छोड़कर भागा ड्राइवर, मामला दर्ज: हादसे के बाद गुजरात पासिंग ट्रक (जीजे 01 केटी 5296) का ड्राइवर अपने वाहन को मौके पर ही छोड़कर भाग निकला। कैंट थाना प्रभारी रोहित डोंगरे ने बताया कि, ट्रक की टक्कर में दो युवकों की मौत हुई है। शवों का पंचनामा बनाकर उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया गया है।

गेहूँ उपार्जन में खरीदी पावती जारी न होने वाले किसानों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। रबी विपणन वर्ष 2026-27 में समर्थन मूल्य पर गेहूँ उपार्जन के दौरान जिन किसानों से गेहूँ खरीदी के उपरांत खरीदी पावती जारी नहीं हुई है, उनकी जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आयुक्त द्वारा जारी पत्र के संदर्भ में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि किसानों को तौल पर्ची जारी किया जाना अनिवार्य है, लेकिन विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कई उपार्जन केन्द्रों द्वारा बिना तौल पर्ची जारी किए किसानों से गेहूँ खरीदा गया है। जिला आपूर्ति अधिकारी ने कहा कि तौल पर्ची जारी नहीं होने के कारण संबंधित किसानों के स्लॉट की वैधता आगे नहीं बढ़ाई जा पा रही है, जिससे किसानों को खरीदी पावती प्राप्त करने में परेशानी हो रही है। ऐसे मामलों के निराकरण हेतु सभी उपार्जन केन्द्रों को निर्देशित किया गया है कि वे केन्द्रवार निर्धारित प्रारूप में उन किसानों की सूची तैयार करें, जिनकी स्लॉट वैधता समाप्त हो चुकी है। उक्त जानकारी एक्सल शीट एवं हार्डकॉपी दोनों स्वरूपों में संबंधित कार्यालय को शीघ्र उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी आयुक्त, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को भेजी जाएगी, ताकि किसानों के स्लॉट की अवधि बढ़ाने की कार्रवाई की जा सके तथा तौल के अनुसार खरीदी पावती ऑनलाइन जारी कराई जा सके। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों एवं उपार्जन केन्द्र प्रभारियों से इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं, जिससे किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो और समर्थन मूल्य खरीदी प्रक्रिया सुचारु रूप से संचालित हो सके।

गंगा दशहरा पर प्रदेश के 10 हजार ग्रामों में निकलेंगी 'जल गंगा कलश यात्राएँ

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा गंगा दशहरा 25 मई 2026 के अवसर पर प्रदेशभर की लगभग 10 हजार पंचायतों में 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के अंतर्गत भव्य 'जल गंगा कलश यात्राएँ' आयोजित की जाएंगी। इस महत्वपूर्ण अभियान की रूपरेखा राज्य स्तरीय प्रशिक्षण कार्यशाला में तैयार की गई। राज्य पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान, वैशाली नगर भोपाल में आयोजित दो दिवसीय 'सी.एम. सोशल इंटर्न प्रशिक्षण कार्यशाला' के समापन सत्र में परिषद के उपाध्यक्ष मोहन नागर ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री के आव्हान पर प्रदेश की प्राचीन जल संरचनाओं–बावड़ी, कुएं, तालाब और सरोवर–के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से यह अभियान संचालित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गंगा दशहरा के दिन जल स्त्रोतों की साफ-सफाई एवं पूजन के उपरांत कलश यात्राएँ निकाली जाएंगी।

अभियान में परिषद की नवांकुर सखियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। साथ ही युवाओं से जल संरक्षण अभियान से सक्रिय रूप से जुड़ने का आग्रह भी किया गया। विदिशा जिले में 35 सेक्टरों और 175 ग्राम समितियों द्वारा होंगे आयोजन मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की ओर से जारी जानकारी के अनुसार विदिशा जिले के सभी 7 विकासखंडों के 35 सेक्टरों में गठित 12 नगर विकास प्रस्फुटन समितियों एवं 175 ग्राम विकास प्रस्फुटन समितियों द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

रतलाम में मेला देखने जा रहे युवक का मिला शव परिजनों ने लगाया कीटनाशक पिलाकर मारने का आरोप

मीडिया ऑडीटर, रतलाम (निप्र)। रतलाम जिले के आलोट में मेला देखने जा रहे 21 साल के युवक का शव संदिग्ध हालात में मंगलवार रात मिला। जब लोगों ने सड़क पर शव देखा तो परिजनों को सूचना दी। ग्रामीण और परिजन पहुंचे। शिनाख्त कर शव लेकर रात 11 बजे आलोट थाने के बाहरसड़क पर रख चक्काजाम कर दिया। परिजनों ने शंका के आधार पर 4 लोगों के नाम बताए है। मृतक का नाम कृष्णपाल (21) पिता लक्ष्मणसिंह निवासी खामरिया है। खामरिया आलोट से तीन किमी दूर है। मंगलवार रात वह करीब 8 बजे अपने घर से आलोट के अनादि कल्पेश्वर महादेव मंदिर पर चल रहे मेले को देखने के लिए घर से निकला था लेकिन गांव से कुछ दूर रात करीब 10 बजे उसका शव संदिग्ध हालात में सड़क पर पड़ा मिला। राहगीरों आते-जाते देखा तो भीड़ लग गई। पता चला कि यह गांव खामरिया का रहने वाला है। तब आलोट थाना पुलिस व परिजनों को सूचना दी।

रात में थाने के बाहर शव रखा : ग्रामीण और परिजनों ने बेटे की हत्या की आशंका जताई और इससे आक्रोशित हो उठे। बड़ी संख्या में लोग शव लेकर आलोट थाने के बाहर पहुंच गए। शव को सड़क पर रख दिया और चक्काजाम कर दिया। आलोट थाना प्रभारी मुनेंद्र गौतम ने परिजनों को समझाने की कोशश की लेकिन आक्रोशित परिजन बेटे की हत्या की बात कहते रहे। परिजनों ने 4 लोगों पर शक जताते हुए बेटे को कीटनाशक पिलाने का संदेह जताया है। रात 12 बजे तक परिजन शव लेकर थाने के बाहर बैठे थे।

यह बात भी सामने आई : मृतक कृष्णपाल मंगलवार आलोट में लगे मेले को देखने गया था। मेले से वह अपने गांव की तरफ लौट रहा था।

रास्ते में कुछ युवकों ने उसे लड़खड़ाता हुआ देखा। उसे इस हालत में तुरंत आलोट के संजीवनी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

चार दिन पहले हुआ था विवाद : यह भी जानकारी सामने आई है कि 4 दिन पहले आलोट के कल्पेश्वर महादेव मंदिर में कृष्ण पाल का कुछ युवकों से झूला झूलने के दौरान विवाद हुआ था। मृतक के परिजनों ने इसकी शिकायत भी आलोट थाने पर की थी। परिजनों ने भी रात में आरोप लगाया कि उसी विवाद के चलते कृष्ण पाल की हत्या की गई है। जानकारी सामने आई है कि युवक जैनम आंचलिया की अनाज की दुकान पर काम करता था।

खंडवा हाईवे पर चलते डंपर में लगी आग फायर ब्रिगेड के इंतजार में लगा रहा जाम

मीडिया ऑडीटर, खंडवा (निप्र)। खंडवा के जावर-मूंदी हाईवे पर बुधवार दोपहर एक चलते डंपर में अचानक आग लग गई। गर्मी बढ़ने और धुआं उठते ही ड्राइवर ने सूझबूझ दिखाते हुए डंपर को सड़क किनारे खड़ा किया और तुरंत कूद गया। इसके बाद वह सीधे ढाबे पर पहुंचा और पानी के लिए मदद मांगी। ढाबा संचालक ने पानी का छिड़काव कराया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। फायर ब्रिगेड के इंतजार में हाईवे पर लंबा जाम लग गया।

सिहाड़ा गांव के पास हुआ हादसा: घटना सिहाड़ा गांव के पास सुदामापुरी की है, जहां लक्की ढाबे के सामने से गुजर रहे क्रेशर रेत से भरे डंपर में आग लग गई। डंपर बालाजी क्रेशर कंपनी का बताया जा रहा है। अचानक आग लगते ही तेज हवा के कारण ऊंची-ऊंची लपटें उठने लगीं। देखते ही देखते हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई। खासकर मूंदी-पुनासा और खंडवा की ओर जा रही यात्री बसों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। भीषण गर्मी में आधे से एक घंटे तक बसें सड़क पर खड़ी रहीं, जिससे यात्रियों को दिक्कत हुई।

सरपंच प्रतिनिधि बोले- शुरुआत में नहीं पहुंची फायर ब्रिगेड : ढाबा संचालक और सिहाड़ा सरपंच प्रतिनिधि हेमंत चौहान ने बताया कि घटना के दौरान वे मौके पर मौजूद थे।

अगले पांच साल तक जारी रहेगी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाखों किसानों को मिलेगा लाभ

प्रभावी क्रियान्वयन के लिये कैबिनेट ने स्वीकृत किये 11608.47 करोड़

मीडिया ऑडीटर, सीहोर (निप्र)। किसान कल्याण वर्ष में मध्यप्रदेश के किसानों को बडा तोहफा देते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को अगले पांच साल तक जारी रखने का फैसला लिया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिये मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में 11608.47 करोड़ रूपये स्वीकृत किये हैं। प्राकृतिक आपदाओं से फसल क्षति होने पर किसानों को सहायता देने योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के क्रियान्वयन, फसल स्थिति और उपज निर्धारण में तकनीकी के उपयोग में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। वर्ष 2023-24 में 35.18 लाख कृषक आवेदनों पर राशि रूपये 961.68 करोड़ का दावा भुगतान किया गया। वर्ष 2024-25 में 35.56 लाख कृषक आवेदनों पर राशि रूपये 275.86 करोड़ का दावा भुगतान किया गया। प्रदेश में वर्ष 2016 से किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। योजना में भागीदार किसानों को फसल नुकसान या क्षति होने पर वित्तीय सहायता मिलती है। खरीफ मौसम में बीमित राशि का 2 प्रतिशत, रबी मौसम में 1.5 प्रतिशत अधिकतम प्रीमियम किसानों द्वारा देय होता है। किसानों द्वारा देय प्रीमियम और बीमांकित प्रीमियम की दर के अंतर को सामान्य प्रीमियम सब्सडि की दर माना जाता है।

इसकी भागीदारी केन्द्र और राज्य द्वारा बराबर वहन की जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा सिंचित और असिंचित जिलों की फसलों में केन्द्र सरकार की प्रीमियम सब्सडि की सीलिंग क्रमशः 25 प्रतिशत और 30 प्रतिशत की सीमा तक रखी गई है। यदि इस सीलिंग के अधिक दरें प्राप्त होती हैं तो अतिरिक्त भार राज्य शासन को वहन करना होता है। मध्यप्रदेश में क्षतिपूर्ती स्तर का 80 प्रतिशत निर्धारित है। आगामी वर्षो में भी सभी फसलों के लिये क्षतिपूर्ती का स्तर 80 प्रतिशत रखा गया है। वैकल्पिक क्रियान्वयन मॉडल प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य अपनी आवश्यकता अनुसार उपयुक्त मॉडल चुन सकता है।

पिपरिया रेलवे स्टेशन पर 18 साल से जल सेवा यात्रियों को ठंडा पानी पिला रहे

मीडिया ऑडीटर, पिपरिया (निप्र)। पिपरिया रेलवे स्टेशन पर पिछले 18 सालों से यात्रियों को ठंडा पानी पिलाने की अनूठी सेवा जारी है। भीषण गर्मी में, जब तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, दर्जनों स्वयंसेवक ट्रेनों के प्लेटफॉर्म पर आते ही यात्रियों की प्यास बुझाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। सुखदेव सिंह कालोटी,विवेक महेश्वरी ने बताया कि यह जनसेवा 18 साल पहले छोटे स्तर पर शुरू हुई थी। धीरे-धीरे लोग इससे जुड़ते गए और अब करीब 150 स्वयंसेवक अलग-अलग ट्रेनों पर जल सेवा प्रदान करने के लिए पहुंचते हैं। इन स्वयंसेवकों में दुकानदार, नौकरीपेशा लोग, छात्र और महिलाएं शामिल हैं, जो अपनी सुविधा के अनुसार स्टेशन पहुंचते हैं। स्वयंसेवक अपने सिर पर गमछा बांधे और हाथों में पानी की कुप्पिया लिए ट्रेनों की खिड़कियों से बाहर निकली बोतलों को तेजी से भरते दिखते हैं।

ट्रेन के धीरे-धीरे चलने के साथ स्वयंसेवकों का दौड़ते हुए बोतलों में पानी भरना एक उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण प्रस्तुत करता है। यह सेवा प्रतिदिन लगभग 40 अप-डाउन ट्रेनों में चलती है। जल सेवा के लिए एक दर्जन से अधिक चलित ट्रॉलियों का उपयोग किया जाता है।

इन ट्रॉलियों में मिट्टी के घड़ों में ठंडा किया गया पानी भरा होता है, जिन्हें फट्टी से पैक टंकियों में रखा जाता है। इन ट्रॉलियों का मुख्य फोकस जनरल बोगियां होती हैं, जिससे पूरी ट्रेन को कवर किया जा सके। प्लेटफॉर्म पर पानी को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के घड़े नेट की छाया में तैयार रखे जाते हैं। रेलवे, आरपीएफ और जीआरपी का भी इस जल सेवा में सहयोग रहता है। रोजाना 20 से 25 हजार लीटर पानी यात्रियों को उपलब्ध कराया जाता है। स्वयंसेवकों का कहना है कि यात्रियों द्वारा तहे दिल से दिया गया शुक्रिया ही उनका सबसे बड़ा पारितोषिक होता है। पिपरिया की यह व्यवस्थित जल सेवा आसपास के स्टेशनों पर कहीं और देखने को नहीं मिलती।

जल गंगा संवर्धन अभियान ग्यारसपुर की ऐतिहासिक जिंद बाबा की बावड़ी में चलाया सफाई अभियान

मीडिया ऑडीटर, विदिशा (निप्र)। प्रदेशव्यापी जल गंगा संवर्धन अभियान अंतर्गत ग्यारसपुर में जल संरक्षण और ऐतिहासिक धरोहरों के संवर्धन को लेकर मध्यप्रदेश जन अभियान परिषद के द्वारा चलाए जा रहे अभियान में आज ग्यारसपुर की प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक जिंद बाबा की बावड़ी में व्यापक साफ-सफाई की गई। हाईवे किनारे स्थित इस प्राचीन बावड़ी की वर्षों से उपेक्षित पड़ी संरचना को स्वच्छ और संरक्षित करने के उद्देश्य से जनभागीदारी के साथ यह विशेष अभियान आयोजित किया गया। अभियान के दौरान बावड़ी परिसर में जमा गंदगी, झाड़ियां एवं कचरे को हटाकर साफ-सफाई की गई। उपस्थित जनसमुदाय ने जल स्त्रोतों के संरक्षण का संदेश देते हुए कहा कि प्राचीन बावड़ियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर होने के साथ-साथ जल संरक्षण का महत्वपूर्ण माध्यम भी हैं। ऐसे ऐतिहासिक जल स्त्रोतों को बचाना आज समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद की जिला समन्वयक पूजा श्रीवास्तव, ब्लॉक समन्वयक सुदेश आचार्य, नवांकुर संस्था युवा परिवर्तन सेवा समिति मणिपुर के शैलेंद्र रघुवंशी, मढी चौबीसा गुलाबगंज के गोलू दांगी, महेश बैरागी, परामर्शदाता राय बहादुर यादव, ओमप्रकाश यादव, मोहनपुर समिति के अध्यक्ष सीताराम कुशवाहा, भागवत लोधी सहित अनेक सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीणजन मौजूद रहे।

क्रिकेटर मोहम्मद शमी को बड़ी राहत

चेक बाउंस मामले में बरी

कोलकाता, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को चेक बाउंस मामले में बड़ी राहत मिली है। शमी को अलीपुर कोर्ट ने उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां द्वारा दायर चेक बाउंस मामले में बरी कर दिया है। क्रिकेटर मोहम्मद की पूर्व पत्नी हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि शमी द्वारा घर के खर्च के लिए दिया गया 1 लाख रुपए का चेक बाउंस हो गया था। बुधवार को अलीपुर कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस मामले में सभी आरोपों से बरी कर दिया है। आईएएनएस से ??बात करते हुए, शमी के वकील सलीम रहमान ने कहा, ÷क्रिकेटर मोहम्मद शमी को चार साल पुराने उस मामले में बरी कर दिया गया है, जिन्हें उनकी पत्नी ने दायर किया था।÷ इस मामले की सुनवाई बुधवार को अलीपुर में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में हुई, जहां शमी को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि साल 2018 में, हसीन जहां ने आरोप लगाया था कि शमी ने उन्हें घरेलू खर्चों के लिए 1 लाख रुपए का चेक दिया था, जो बाद में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का रुख किया और शमी के खिलाफ मामला दर्ज कराया। इस मामले के अलावा, उन्होंने शमी और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई अन्य शिकायतें भी दर्ज कराई थीं।

बुधवार को शमी कोर्ट में पेश हुए। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए शमी ने कहा कि उन्हें पहले से ही पता था कि फैसला उनके पक्ष में आएगा, क्योंकि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। उन्होंने कहा, ÷मुझे जितने भी पैसे देने थे, मैंने उसका एक-एक रुपया चुका दिया है। चाहे मैदान के अंदर की बात हो या बाहर की, मैं हमेशा हर स्थिति को अपनी पूरी क्षमता से संभालने की कोशिश करता हूं।÷

शमी फिलहाल इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अपनी अलग रह रही पत्नी के साथ चल रहे कानूनी विवादों के चलते वे लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं।

भरण-पोषण और गुजारा भत्ते को लेकर शमी और हसीन जहां के बीच चल रही कानूनी लड़ाई अभी भी जारी है। कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, शमी फिलहाल हसीन जहां को प्रतिमाह 1.5 लाख रुपए और अपनी बेटी की देखभाल और परवरिश के लिए 2.5 लाख रुपए का भुगतान करते हैं।

बाद में हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और यह दलील दी कि यह राशि घरेलू खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। शीर्ष अदालत ने शमी और पश्चिम बंगाल सरकार, दोनों को नोटिस जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान, अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि क्या एक मां और बेटी के भरण-पोषण के लिए प्रति माह 4 लाख रुपए की राशि अपर्याप्त है।

विराट ने बताया, किन कारणों से छोड़ी थी कप्तानी

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल टेस्ट कप्तानों में शामिल रहे विराट कोहली ने उन कारणों का खुलासा किया है जिनके कारण उन्होंने राष्ट्रीय टीम की कप्तानी छोड़ी थी। कोहली ने कहा कि नेतृत्व और बल्लेबाजी के लगातार दबाव ने उन्हें पूरी तरह से थका दिया था, जिसके बाद उन्हें लगा जैसे उनके पास देने के लिए कुछ नहीं बचा है। उन्होंने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि किस तरह एक कप्तान हमेशा सवालों के घेरे में रहता है, चाहे वह जीते या हारे।

कोहली ने बताया कि कप्तानी और बल्लेबाजी दोनों में अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश ने उनकी सारी ऊर्जा खींच ली। उन्होंने उस असाधारण मानसिक दबाव का जिक्र किया जिसमें एक कप्तान हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। अगर आप जीते और आपने रन नहीं बनाए तो आपसे आपके प्रदर्शन को लेकर सवाल किए जाएंगे। और अगर आपने प्रदर्शन किया और टीम नहीं जीती तब आप पर परिणामों को लेकर सवाल उठेंगे, कोहली ने स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि वह हमेशा इन दोनों चुनौतियों के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करते रहे।

विराट ने बताया कि वह पहले बल्लेबाजी इकाई के केंद्र बिंदु बने और फिर टीम के नेतृत्व के भी। उन्हें शुरुआत में यह अंदाजा ही नहीं हुआ कि इन दोनों भूमिकाओं का उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर कितना बड़ा भार पड़ेगा। मैं बहुत ज्यादा प्रेरित था कि भारतीय क्रिकेट को शिखर पर बनाए रखना है, इसलिए मैंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने कहा। लेकिन जब मैंने कप्तानी छोड़ी, तब मैं पूरी तरह से खप चुका था, जैसे मेरे पास देने के लिए अब कुछ और बचा ही नहीं होज वह भयंकर था।

इस दौरान विराट कोहली ने मुख्य कोच राहुल द्रविड़ और बल्लेबाजी कोच विक्रम राठौर के प्रति अपने गहरे आभार को भी व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि जब वह 2021 से 2022 के बीच टेस्ट क्रिकेट में अपने करियर के एक कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब इन दोनों ने उनका बहुत समर्थन किया।

2016 से 2019 के शानदार प्रदर्शन के बाद, कोहली का टेस्ट औसत 2021 में 28.21 और 2022 में 26.5 तक गिर गया था। हालांकि, 2023 में उन्होंने वापसी करते हुए 8 टेस्ट में 55.91 की औसत से 671 रन बनाए। कोहली ने कहा, राहुल भाई और विक्रम राठौरज मैं यह कई बार कह चुका हूं। मैं जब भी उन्हें देखता हूं, जब भी उनसे मिलता हूं, तो मैं हमेशा उनको अपने दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं।

मोहन बागान, केरल ब्लास्टर्स समेत कई क्लबों को नहीं मिला एआईएफएफ प्रीमियर 1 लाइसेंस

नई दिल्ली, एजेंसी। भारतीय फुटबॉल के कई प्रमुख क्लबों के 2026-27 सीजन के लिए प्रीमियर 1 क्लब लाइसेंस आवेदन को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन (एआईएफएफ) ने खारिज कर दिया है। इनमें मोहन बागान सुपर जायंट, केरल ब्लास्टर्स एफसी और ओडिशा एफसी जैसे मशहूर क्लब शामिल हैं। 17 मई को एआईएफएफ की क्लब लाइसेंसिंग समिति, फर्स्ट इंस्टेंस बॉडी (सीएलसी-एफआईबी) की बैठक में यह घोषणा की गई कि स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली, ओडिशा एफसी, मोहन बागान सुपर जायंट, चेन्नईयिन एफसी, केरल ब्लास्टर्स एफसी, मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब और इंटर काशी के लाइसेंस खारिज कर दिए गए हैं। शासी निकाय ने स्पष्ट किया कि ये क्लब इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, या लागू नियमों के तहत राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए छूट का अनुरोध कर सकते हैं। एक आधिकारिक बयान में, एआईएफएफ ने कहा कि जिन क्लबों के आवेदन खारिज कर दिए गए हैं, वे लाइसेंसिंग नियमों के अनुसार, या तो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं, या राष्ट्रीय क्लब प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए छूट का अनुरोध कर सकते हैं।

इस बीच, नॉर्थईस्ट यूनाइटेड एफसी, ईस्ट बंगाल एफसी, जमशेदपुर एफसी, मुंबई सिटी एफसी, बेंगलुरु एफसी, एफसी गोवा और पंजाब एफसी को कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस प्रदान किए गए। हालांकि, इन क्लबों ने लाइसेंसिंग प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन इन शर्तों से यह पता चलता है कि कुछ मानदंडों या अनुपालन शर्तों को अभी भी पूरा करने की जरूरत है।

भारतीय क्लब लाइसेंसिंग प्रणाली एक वार्षिक जरूरत है, जिसका उद्देश्य देश के क्लबों के बीच व्यावसायिकता, बुनियादी ढांचे, प्रशासन और खेल मानकों में सुधार करना है। यह लाइसेंसिंग ढांचा एआईएफएफ और एशियाई फुटबॉल परिसंघ द्वारा स्वीकृत घरेलू और एशियाई, दोनों तरह की प्रतियोगिताओं में भाग लेने की पात्रता निर्धारित करता है।

इस प्रणाली के तहत लाइसेंस को दो श्रेणियों में बांटा गया है– इंडियन सुपर लीग क्लबों के लिए प्रीमियर 1 और भारतीय फुटबॉल लीग संरचना के क्लबों के लिए प्रीमियर 2। इस प्रक्रिया में क्लबों का मूल्यांकन वित्तीय स्थिति, कानूनी मामलों, बुनियादी ढांचे, स्टाफ और युवा विकास समेत कई मानकों के आधार पर किया जाता है।

मालविका बंसोड़ टूर्नामेंट से बाहर, चालिहा से उम्मीदें जिंदा

कुआलालंपुर, एजेंसी। मलेशिया मास्टर्स 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत की स्टार शटलर Malvika Bansod का सफर दूसरे दौर में खत्म हो गया। कुआलालंपुर में खेले गए मुकाबले में उन्हें डेनमार्क की आठवीं वरीयता प्राप्त खिलाड़ी लाइन कजर्सफेल्ट के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारतीय खिलाड़ी Ashmita Chaliha ने शानदार जीत दर्ज कर भारत की उम्मीदों को कायम रखा।

पहला गेम जीतने के बाद मैच गंवा बैठीं मालविका

विश्व रैंकिंग में 51वें स्थान पर मौजूद मालविका बंसोड़ ने मुकाबले की शानदार शुरुआत की। उन्होंने पहले गेम में आक्रामक खेल दिखाते हुए 21-16 से जीत हासिल की और मैच पर मजबूत पकड़ बना ली। पहले गेम के दौरान मालविका ने शुरुआत से बढ़त बनाए रखी और इंटरवल तक 11-6 से आगे थीं। इसके बाद उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखते हुए गेम अपने नाम किया।

दूसरे गेम में बदला मैच का रुख

पहला गेम हारने के बाद डेनमार्क की लाइन कजर्सफेल्ट ने जोरदार वापसी की। दूसरे गेम में उन्होंने शुरुआती आठ अंक लगातार जीतकर मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। मालविका इस दबाव से उबर नहीं सकीं और दूसरा गेम 21-8 से गंवा बैठीं।निर्णायक गेम में एक समय मालविका 11-8 से आगे थीं, लेकिन इसके बाद कजर्सफेल्ट ने लगातार अंक जुटाते हुए मुकाबला 21-15 से अपने नाम कर लिया।

अश्मिता चालिहा ने बढ़ाया भारत का मान

दूसरी ओर अश्मिता चालिहा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मलेशिया की स्टार खिलाड़ी गोह जिन वेई को सीधे गेमों में हराया। अश्मिता ने मुकाबला 21-13, 21-16 से जीतकर महिला एकल वर्ग में भारत की चुनौती जिंदा रखी।

अफगानिस्तान सीरीजः प्रिंस, गुरनूर और हर्ष को पदार्पण का इंतजार

मुंबई, एजेंसी। भारतीय क्रिकेट टीम में नए चेहरों को मौका दिए जाने का सिलसिला जारी है। अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी तीन एकदिवसीय मैचों की श्रृंखला के लिए जिन खिलाड़ियों को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है, उनमें प्रिंस यादव, गुरनूर बराड़ और हर्ष दुबे शामिल हैं। इन तीनों युवा प्रतिभाओं को घरेलू क्रिकेट में उनके लगातार और शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है, और अब वे अंतिम ग्यारह में जगह बनाने की उम्मीद कर रहे हैं। यह तीनों खिलाड़ी अपने प्रभावशाली लिस्ट ए रिकॉर्ड के दम पर राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने में कामयाब रहे हैं। उनकी प्रतिभा और समर्पण ने चयनकर्ताओं का ध्यान खींचा है, और उन्हें उम्मीद है कि वे अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी अपनी छाप छोड़ने में सफल रहेंगे।

प्रिंस यादव~ दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने हाल ही में अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया है। आईपीएल 2026 में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) का प्रतिनिधित्व करते हुए, उन्होंने अपनी गति और सटीकता से दिग्गज बल्लेबाजों को भी असहज किया। उन्होंने आईपीएल के उस सीज़न में 12 मैचों में 16 विकेट झटके थे। दिल्ली के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले प्रिंस का लिस्ट ए रिकॉर्ड भी बेहतरीन है, जहां उन्होंने 14 मैचों में 29 महत्वपूर्ण विकेट अपने नाम किए हैं। प्रिंस की आकांक्षा है कि वे इस अवसर का लाभ उठाकर बेहतर प्रदर्शन करें और जल्द ही विश्व कप टीम में भी जगह बना सकें।

गुरनूर बराड़~ पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे दाहिने हाथ के तेज गेंदबाज गुरनूर बराड़ को भी भारतीय टीम में पहला अवसर दिया गया है। आईपीएल 2026 में उन्हें केवल एक मैच खेलने का मौका मिला था, जिसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला, लेकिन पंजाब के लिए घरेलू क्रिकेट में उनका प्रदर्शन सराहनीय रहा है। गुरनूर ने अपने 9 लिस्ट ए मैचों में 12 विकेट लेकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। उनकी यॉर्कर और स्विंग गेंदें बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें पैदा करती हैं।

हर्ष दुबे~ 23 वर्षीय हर्ष दुबे तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। हर्ष एक गेंदबाजी ऑलराउंडर हैं, जो अपनी बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी के साथ-साथ निचले क्रम में महत्वपूर्ण बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। आईपीएल 2026 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए खेलते हुए, उन्होंने 8 मैचों में 8 विकेट लिए थे। विदर्भ के लिए घरेलू क्रिकेट खेलने वाले हर्ष का लिस्ट ए रिकॉर्ड उनकी बहुमुखी प्रतिभा का प्रमाण है। उनके 30 लिस्ट ए मैचों में 31 विकेट हैं, और बल्लेबाजी में उन्होंने 17 पारियों में 2 अर्धशतक के साथ कुल 296 रन बनाए हैं। वे गेंदबाजी के साथ ही बल्लेबाजी में भी टीम के लिए बेहतर विकल्प साबित हो सकते हैं।

अब टी20 फॉर्मेट में खेला जाएगा अंडर-23 वनडे टूर्नामेंट

नई दिल्ली, एजेंसी। आगामी 2026/27 घरेलू सीजन में अंडर-23 पुरुषों के वनडे टूर्नामेंट की जगह टी20 फॉर्मेट लेगा, जबकि कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी विजेता बनाम शेष भारत का मैच घरेलू सीजन के कैलेंडर में वापस आ जाएगा। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बुधवार को यह जानकारी दी। 2026-27 के घरेलू सीजन में पुरुषों और महिलाओं के क्रिकेट में कई आयु-वर्ग श्रेणियों में कुल 1,788 मैच खेले जाएंगे। इस सीजन की शुरुआत प्रतिष्ठित दलीप ट्रॉफी से होगी, जो 23 अगस्त से 10 सितंबर तक बेंगलुरु में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में खेली जाएगी। इसके बाद 1 अक्टूबर से ईरानी कप की शुरुआत होगी। यह संभवतः जम्मू या श्रीनगर में खेला जाएगा, क्योंकि जम्मू और कश्मीर अभी रणजी ट्रॉफी के मौजूदा विजेता हैं, जिसे उन्होंने इस साल की शुरुआत में हुबली में जीता था। रणजी ट्रॉफी दो-चरणों वाले फॉर्मेट में जारी रहेगी। एलीट ग्रुप में 32 टीमें चार ग्रुप में होंगी और प्लेट ग्रुप में छह टीमें सामान्य होम-एंड-अवे फॉर्मेट में खेलेंगी। कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी विजेता बनाम शेष भारत का मुकाबला 1-4 अक्टूबर को फिर से खेला जाएगा।

मेंस अंडर-23 स्टेट ए ट्रॉफी को टी20 फॉर्मेट में बदलने के अलावा, विजी ट्रॉफी वनडे प्रतियोगिता के बजाय टी20 फॉर्मेट में खेली जाएगी। कूच बिहार ट्रॉफी (एलीट ग्रुप) के नॉकआउट चरण बेंगलुरु और मैसूर में आयोजित किए जाएंगे, ताकि जनवरी के दौरान मैचों में प्रतिस्पर्धी संतुलन बना रहे।

साल्ट आईपीएल प्लेऑफ के लिए वापसी करेंगे

आरसीबी को मिली राहत

बेंगलुरु, एजेंसी। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के आक्रामक बल्लेबाज फिल सॉल्ट अब चोट से उबर गये हैं और प्लेऑफ मुकाबलों के लिए वापसी करने जा रहे हैं। साल्ट की वापसी की उम्मीद से आसीबी के खेमे में उत्साह का माहौल है। साल्ट टीम के लिए इसलिए बेहद अहम है क्योंकि वह सलामी बल्लेबाज के तौर पर टीम को तेज शुरुआत देते हैं। लीग के शुरुआती मैचों के दौरान ही उंगली की चोट के कारण वह इलाज के लिए इंग्लैंड लौट गये थे पर अब वह दौरान में शामिल होने जा रहे हैं।

आरसीबी प्लेऑफ में पहुंच गयी है और ऐसे में उसे अब साल्ट जैसे बल्लेबाज की जरुरत है। नॉकआउट चरण के दबाव भरे मैचों में साल्ट जैसे अनुभवी खिलाड़ी का होना टीम के लिए लाभदायक रहेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार सॉल्ट इस सप्ताह आरसीबी कैंप से जुड़ने के बाद अपनी फिटनेस पर काम करना शुरू कर देंगे। उनके प्लेऑफ मुकाबलों तक पूरी तरह से मैच फिट होने की पूरी संभावना है।

इस सत्र में चोटिल होने से पहले सॉल्ट शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने लीग में खेली गई 6 पारियों में कुल 202 रन बनाए थे। इस दौरान उनका औसत 33.66 और विध्वंसक स्ट्राइक रेट 168.33 का रहा था। सॉल्ट ने इस सीजन में दो शानदार अर्धशतक भी लगाये थे।

आईपीएल 2026: केकेआर की कसी हुई गेंदबाजी, सिर्फ 147 रन बना सकी मुंबई इंडियंस

कोलकाता, एजेंसी। मुंबई इंडियंस (एमआई) ने बुधवार को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 65वें मैच में जीत के लिए 148 रन का टारगेट रखा है। ईडन गार्डन्स में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई इंडियंस ने 8 विकेट खोकर 147 रन बनाए। इस टीम को तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर रयान रिकेल्टन के रूप में महज 17 के स्कोर पर पहला झटका लगा। रिकेल्टन 6 रन बनाकर पवेलियन लौटे। तीसरे ओवर की अंतिम गेंद पर नमन धीर (0) भी आउट हो गए। एमआई ने 41 के स्कोर तक रोहित शर्मा (15) और सूर्यकुमार यादव (15) के विकेट भी गंवा दिए।

मुंबई इंडियंस ने 8 ओवरों में 4 विकेट खोकर 57 रन बना लिए थे, जिसके बाद बारिश के चलते खेल रुका। जब फिर से मैच शुरू हुआ, तो ओवरों में किसी भी तरह की कटौती नहीं की गई।

यहां से हार्दिक पांड्या ने तिलक वर्मा के साथ पांचवें विकेट के लिए 49 गेंदों में 43 रन की साझेदारी करते हुए टीम को 84 के स्कोर तक पहुंचाया। तिलक 32 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट हुए, जबकि कप्तान हार्दिक पांड्या ने 26 रन का योगदान टीम के खाते में दिया। कॉर्बिन बॉश 18 गेंदों में 2 छक्कों और 3 चौकों के साथ 32 रन बनाकर नाबाद रहे।

विपक्षी खेमे से सौरभ दुबे, कैमरून ग्रीन और कार्तिक त्यागी ने 2-2 विकेट हासिल किए। सुनील नरेन को 1 विकेट हाथ लगा। कोलकाता नाइट राइडर्स इस मैच को जीतकर प्लेऑफ की उम्मीदें कायम रखना चाहेगी। 12 में से 5 मैच जीतकर केकेआर प्वाइंट्स टेबल में 8वें स्थान पर है। वहीं, एमआई ने 12 में से 8 मैच गंवा दिए हैं। यह टीम 9वें स्थान पर है।

अजिंक्य रहाणे की कप्तानी में कोलकाता नाइट राइडर्स अंगकृष रघुवंशी (विकेटकीपर), कैमरून ग्रीन, रोवमैन पॉवेल, मनीष पांडे, रिंकू सिंह, सुनील नरेन, अनुकूल रॉय, कार्तिक त्यागी, वरुण चक्रवर्ती और सौरभ दुबे के साथ इस मैच में उतरी है।

मुंबई इंडियंस की प्लेइंग इलेवन में रयान रिकेल्टन, रोहित शर्मा (विकेटकीपर), नमन धीर, सूर्यकुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विल जैक, कॉर्बिन बॉश, दीपक चाहर, जसप्रीत बुमराह और रघु शर्मा शामिल हैं।

सडक सुरक्षा समिति की बैठक में जीरो फेटालिटी प्रोग्राम एवं पीएम राहत योजना पर विशेष जोर

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के 6 जिले जहां सडक दुर्घटनायें और फैटालिटी अधिक संख्या में हो रही है उन जिलो को जीरो फेटेलिटी प्रोग्राम से जोडा गया है जिनमें धार सतना सागर रीवा, जबलपुर एवं खरगौन जिले शामिल है सडक दुर्घटनाओं को रोकने कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में गुरूवार को सतना कलेक्ट्रेट में सडक विभागों और सेव लाइफ फाउण्डेशन के प्रतिनिधियों के साथ सडक सुरक्षा समिति की बैठक में जीरो फेटालिटी प्रोग्राम एवं कैशलेस ट्रीटमेंट की पीएम राहत योजना के क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया गया। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, एसडीएम राहुल सिलाडिया, आरटीओ संजय श्रीवास्तव, डीएचओ डॉ. नलिनी शुक्ला,

डीएसपी ट्रैफिक संजय खरे भी उपस्थित रहे सेव लाइफ फाउण्डेशन के प्रतिनिधि श्री साहिल और गौतम पंढारे ने सडक दुर्घटनाओं के संबंध में जिले के जीरो फेटालिटी स्कोर इण्डेक्स का प्रस्तुति करण किया। कलेक्टर ने कहा कि रोड सेफ्टी और जीरो फेटालिटी प्रोग्राम में शामिल अधिकारियों का वाट्सअप ग्रुप बनाकर समन्वय और सूचनाओं का आदान-प्रदान करें। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया कि सतना जिले के आयुष्मान योजना के तहत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों सहित अन्य प्रमुख निजी अस्पताल और नर्सिंग होम को कैशलेस ट्रीटमेंट के लिए पीएम राहत योजना से जोडा जाये। जीरो फैटालिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के क्रियान्वयन को इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट एक्सन प्लान और ट्रामा फेसलिटी तीनों भागों के समुचित समन्वय से और तेजी लाई जा सकती है सतना जिले में जीरो फैटालिटी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के प्रभावी संचालन पर्यवेक्षण एवं डीडीएचआई आधारित कार्ययोजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए अपर कलेक्टर सतना को नोडल अधिकारी और डीएसपी ट्रैफिक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर ने कहा कि सडक सुरक्षा समिति की बैठक में एम्बुलेंस सेवा के संचालक को भी उपस्थित कराया जायेसेव लाइफ फाउण्डेशन के प्रतिनिधि ने पावर प्रजेन्टेशन में बताया कि भारत में औसत रूप से सडक दुर्घटनाओं में प्रतिदिन 500 मौते होती है। सतना जिले में वर्ष 2024 में सडक दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या 518 रही जबकि वर्ष 2025 में यह आंकडा 464 रहा है सतना जिले में सडक दुर्घटनाओं से संभावित क्षेत्रों में 6 क्रिटिकल लोकेशन चिन्हांकित की गई है। सेव लाइफ फाउण्डेशन की टीम सतना जिले के भ्रमण के दौरान सडक विभाग के अधिकारियों के साथ दुर्घटना संभावित लोकेशन का मौका निरीक्षण कर रही है।

झूलेलाल बेड़ा पार के जयकारों से गूंजी सिंधी कॉलोनी, श्री झूलेलाल कथा का समापन

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। बाबा मेहरशाह दरबार साहिब में पुरषोत्तम मास के अवसर पर सनातन भक्ति महोत्सव के पावन आयोजन में श्रद्धालुओं ने भक्ति की गंगा में डुबकी लगाई। महंत स्वामी पुरषोत्तमदास जी के सानिध्य में चल रहे धार्मिक कार्यक्रमों में सपरिवार श्रद्धालु शामिल होकर श्री झूलेलाल सांई जी की कथा का लाभ उठा रहे हैं। संतश्री ने कहा कि इष्टदेव की कथा सुनने से संसार के सभी पुण्य लाभ प्राप्त होते हैं कथा का आनंद लेने के लिए बाबा रूद्रनाथ जी, महराज घनश्याम दास शर्मा सहित कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। बाबा मेहरशाह दरबार साहिब के प्रमुख प्रवक्ता राजकुमार बजाज ने बताया कि आज छत्तीसगढ़ (चकरभाठा) से पधारे संत लालसांई जी ने दूसरे दिन भगवान श्री झूलेलाल सांई जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए बताया कि झूलेलाल जी ने अन्याय को समाप्त करने और सभी भक्तों में दया, करूणा तथा ईश्वर भक्ति करने का मार्ग प्रशस्त किया संत श्री लालसांई जी ने भगवान श्री

झूलेलाल के जन्मोत्सव का प्रसंग सुनाते ही पूरी सिंधी कॉलोनी में 'बेड़ा पार के जयकारों' से गूंज उठी। चारों ओर 'उडेरोलाल अमर रहे' और 'पल्लव वारो अमर रहे' के उद्घोष से वातावरण भक्तिमय हो गया संत श्री लालसांई जी ने विशेष रूप से युवाओं को भगवान झूलेलाल के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण संदेश दिए। उन्होंने कहा कि प्रेम और शांति ही सबसे बड़ा धर्म है, हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। आज भी सिंधी समाज में झूलेलाल सांई जी आस्था, एकता और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में पूजे जाते हैं कार्यक्रम के समापन के साथ ही कथा का समापन हुआ और श्रद्धालुओं ने भगवान झूलेलाल की भक्ति में मन को लीन रखते हुए धार्मिक आयोजनों का लाभ उठाया।

चित्रकूट: पंच प्रयाग घाट पर शराब पीते 7 युवक गिरफ्तार, बोलेरो और शराब जब्त

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। चित्रकूट के पंच प्रयाग घाट, सती अनुसुइया पर कुछ युवकों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर शराब पीते जाने की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सात युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने बताए गए स्थान पर घेराबंदी कर रेड की और नशे में धुत पाए गए युवकों को हिरासत में लिया आरोपियों की पहचान अजय द्विवेदी (28), दीपू पाण्डेय (28), अमन पाण्डेय (16), सौरभ द्विवेदी (23), सुभम द्विवेदी (24), संजय कुमार तिवारी (32) और सूरज उर्फ कृष्णकान्त मिश्रा (16) के रूप में हुई। सभी आरोपी सकरौली, थाना पहाड़ी, जिला चित्रकूट के निवासी हैं पुलिस ने मौके से एक बोतल सिग्नेचर अंग्रेजी शराब (750 एमएल), एक आधी खाली बोतल सिग्नेचर अंग्रेजी शराब (375 एमएल), एक अधभरी किंगफिशर बियर (650 एमएल) 08 प्लास्टिक के डिस्पोज़ल गिलास, 10 सिगरेट, दो अधजली सिगरेट और 2 लीटर की प्लास्टिक बोतल में पानी जब्त किया। इसके अलावा आरोपियों की बोलेरो जीप क्रमांक क्र96ए5216 भी जब्त की गई तफ्तीश में पता चला कि बोलेरो चालक अजय द्विवेदी वाहन के वैध दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर पाए। इसके चलते चालक पर धारा 130/177(1) व 130/177(3) एम.व्ही. एक्ट का उल्लंघन पाया गया। सभी आरोपियों ने सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान कर धारा 36(बी) आबकारी एक्ट का उल्लंघन किया चूंकि आरोपियों का अपराध जमानती और सात वर्ष से कम सजा का है, पुलिस ने मौके पर ही धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. की नोटिस थमाई और उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने के लिए कहा। थाने लौटने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों से अपील की है कि सार्वजनिक स्थान पर शराब का सेवन न करें और कानून का पालन करें।

विज्ञान मंथन यात्रा: इसरो भ्रमण से लौटे विद्यार्थियों ने कलेक्टर और एसपी से साझा किए अनुभव

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के शैक्षणिक और प्रेरणादायी भ्रमण से लौटे विद्यार्थियों ने आज सतना कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस. और पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह से सौजन्य भेंट कर अपने अनुभव साझा किए इस अवसर पर एक्सीलेंस स्कूल वेंकट क्रमांक-1 के 13 छात्र-छात्राओं ने प्राचार्य कमलेश सिंह बघेल और मार्गदर्शक शिक्षकों डॉ. रामानुज पाठक नविता जायसवाल एवं नंदकिशोर पाठक के साथ यात्रा का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक सतना, नगर निगम आयुक्त शहर सिंह मीणा और सिटी मजिस्ट्रेट राहुल सिलाडिया भी उपस्थित रहे अधिकारियों ने विद्यार्थियों की उपलब्धियों की सराहना की और उन्हें विज्ञान एवं अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया सतना जिले से विज्ञान मंथन यात्रा के लिए कुल 24 विद्यार्थियों का चयन

किया गया था जिसमें सर्वाधिक 16 विद्यार्थियों का चयन एक्सीलेंस स्कूल वेंकट क्रमांक-1 से हुआ इसके अतिरिक्त सांदीपनी विद्यालय बगहा के 2 और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चौराहटा के 6 विद्यार्थियों ने भी इस वैज्ञानिक यात्रा में भाग लिया कलेक्टर ने विद्यार्थियों से बातचीत करते हुए इसरो के विभिन्न केंद्रों वैज्ञानिक गतिविधियों और अंतरिक्ष अनुसंधान से जुड़े अनुभवों के बारे में जानकारी प्राप्त की उन्होंने छात्रों से चेन्नई के मौसम वैज्ञानिक वातावरण और व्यवस्थाओं के विषय में चर्चा की और पीएसएलवी एवं जीएसएलवी लॉन्च व्हीकल के बीच अंतर पूछकर उनकी वैज्ञानिक समझ को परखा कलेक्टर ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत आज विज्ञान और अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व के अग्रणी देशों में शामिल है उन्होंने छात्रों से विज्ञान में कैरियर बनाने जिज्ञासा बनाए रखने और निरंतर अध्ययन करने का आह्वान किया। पुलिस अधीक्षक हंसराज सिंह ने भी विद्यार्थियों के अनुभव सुने और उन्हें बड़े सपने देखने तथा कठिन परिश्रम और अनुशासन से उन्हें साकार करने के लिए प्रेरित किया इस अवसर पर विद्यार्थियों के साथ समूह छायाचित्र भी लिया गया। इसरो भ्रमण हेतु चयनित विद्यार्थियों में कक्षा 12 से पल्लवी राठौड़, रिषिका त्रिपाठी, रुद्राक्ष त्रिपाठी, तोषी गौतम कक्षा 11 से आदित्य पांडेय, अखंड प्रताप यादव, कंचन चौधरी, रितिक तिवारी, नेहा पटेल; कक्षा 10 से कृष्णा गुप्ता, मोहिना गुप्ता, प्राची कुशवाहा, प्रियंकज कुशवाहा, राधे गुप्ता, अंश राज सिंह, राजवीर सिंह तोमर एवं उत्कर्ष गुप्ता शामिल थे इस शैक्षणिक भ्रमण ने विद्यार्थियों को विज्ञान, नवाचार और अंतरिक्ष अनुसंधान की नई संभावनाओं से अवगत कराया और उनकी वैज्ञानिक चेतना और अनुसंधान की प्रवृत्ति को मजबूत किया।

कांग्रेस सेवादल ने राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर किया आयोजन

मीडिया ऑडीटर, मैहर (निप्र)। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, पंचायती राज व सूचना प्रौद्योगिकी के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता और भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि कांग्रेस सेवादल मैहर के तत्वावधान में मनाई गई। कार्यक्रम स्थानीय कांग्रेस कार्यालय में आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस सेवादल जिला अध्यक्ष अरुण तनय मिश्र और वरिष्ठ कांग्रेस नेता केशव प्रसाद चौरसिया की गरिमामयी उपस्थिति रही जिला अध्यक्ष अरुण तनय मिश्र ने अपने उद्बोधन में स्व. राजीव गांधी को कोटि-कोटि नमन करते हुए कहा कि उन्होंने मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की और 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि

गांधी जी ने अपने कार्यकाल के आरंभ में ही देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के लिए मजबूत आर्थिक और सैन्य शक्ति के महत्व को समझा अरुण तनय मिश्र ने राजीव गांधी के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि 1985 में उन्होंने सिख उग्रवाद को शांत करने के लिए अकाली दल के नेता हरचंद सिंह लोगोंवाल के साथ समझौता किया, जिसे 'राजीव-लोगोंवाल समझौता' कहा जाता है। इसके अलावा उन्होंने टेलीफोन और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार कर लोगों को बेहतर सेवाएं प्रदान की वरिष्ठ नेता केशव प्रसाद चौरसिया ने कहा कि राजीव गांधी ने भारत में एक नई आर्थिक नीति लागू की, जिसने निजी क्षेत्र को बढ़ावा दिया और अर्थव्यवस्था को खुले बाजार के लिए तैयार किया। नई आर्थिक नीतियों ने भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था को मजबूती दी और देश को वैश्विक मंच पर स्थापित किया इस अवसर पर ऋषिकेश पांडे, मुकेश सेन, सुषमा अरजरिया, जनक दुलारी शुक्ला, सुनील कोरी, लक्ष्मीकांत अर्जरिया, अश्विनी द्विवेदी, उमाशंकर तिवारी, अभिषेक सेन, अंबुज तनय, अरुण कुशवाहा, रतन सेन, मुमताज मोहम्मद, रवि नंदन प्रजापति, रामू लाल, कंचू लाल सियानंद, रजक सहित कई अन्य लोग उपस्थित रहे और कार्यक्रम को

सतना का 32 करोड़ का ISBT बना शोपीस शिलापट्ट तक सीमित रही राजनीति

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। करोड़ों रुपए की लागत से बनाए गए अत्याधुनिक इंटर-स्टेट बस टर्मिनल आज वीरानी का शिकार बन गया है 32 करोड़ रुपए खर्च कर तैयार इस बस स्टैंड को जनता अब सिर्फ नेताओं के नाम शिलापट्ट में दर्ज कराने के प्रतीक के रूप में देख रही है स्थानीय लोगों का कहना है कि नया बस स्टैंड लगभग खाली पड़ा है, जबकि पुराना बस स्टैंड जाम, भीड़ और अव्यवस्था का केंद्र बना हुआ है। सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े निवेश के बावजूद शासन और प्रशासन बस ऑपरेटरों और निजी वाहनों के दबाव के आगे क्यों बेबस नजर आ रहे हैं स्थानीय यात्रियों का कहना है कि नए ISBT में न तो यात्री सुविधाओं का सही इस्तेमाल हो रहा है और न ही बसों का नियमित संचालन। इससे न

सिर्फ संसाधनों की बर्बादी हो रही है बल्कि आम जनता को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के बड़े प्रोजेक्टों में योजना और संचालन के बीच तालमेल होना बेहद जरूरी है। केवल भव्य निर्माण और शिलापट्ट तक सीमित राजनीति से इन परियोजनाओं का उद्देश्य अधूरा रह जाता है नगर निगम और परिवहन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, बस ऑपरेटरों और शहर में व्यस्त मार्गों के चलते नया ISBT पूरी तरह संचालित नहीं हो पा रहा है। प्रशासनिक लापरवाही और सुचारू योजना की कमी के कारण यह अत्याधुनिक प्रोजेक्ट अब जनता के लिए 'शोपीस' बनकर रह गया है स्थानीय लोगों की मांग है कि नए ISBT को पूरी तरह संचालित किया जाए और यात्री सुविधाओं के साथ बस संचालन में सुधार किया जाए। ताकि करोड़ों रुपए का यह निवेश केवल शिलापट्ट तक सीमित न रहे, बल्कि शहर और यात्रियों के लिए उपयोगी साबित हो।

सेल्समैन समेत प्रबंधक पर एफआईआर एसडीएम ने जारी किया वसूली का आदेश

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। कलेक्टर मैहर बिदिशा मुखर्जी के निर्देशन में खाद्यान्न वितरण में अनियमितता बरतने पर सेवा सहकारी समिति बरा खुर्द द्वारा संचालित शासकीय उचित मूल्य दुकान गोरइया के विक्रेता धनीराम दहिया और समिति प्रबंधक कमलेश विश्वकर्मा के विरुद्ध थाना बदेरा में एफआईआर दर्ज कराई गई है। संबंधित दुकान की विक्रेता और समिति प्रबंधक द्वारा जनवरी से जून 2026 माह तक का उपभोक्ताओं का मशीन में अंगूठा लगाने के बावजूद खाद्यान्न का वितरण नहीं किया गया। एसडीएम मैहर दिव्या पटेल ने संबंधित दुकान के विक्रेता धनीराम दहिया और समिति प्रबंधक कमलेश विश्वकर्मा के खिलाफ वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की कीमत का 23 लाख 25 हजार 901 रुपए की वसूली भी निकाली है। मामले की जांच के बाद कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी प्रियंका अग्रवाल ने पुलिस में एफआईआर दर्ज करा दी है। बहुउद्देशीय सेवा सहकारी समिति बरा खुर्द की दुकान गौरईया द्वारा 15 लाख 52 हजार 691 रुपए मूल्य का 552 क्विंटल गेहूं, 7 लाख 27 हजार 861 रुपए मूल्य का 181 क्विंटल चावल, 16 हजार 704 रूपये मूल्य की 3.48 क्विंटल शक्कर और 28 हजार 645 मूल्य का 29.38 क्विंटल नमक का वितरण नहीं किया गया। संबंधित विक्रेता और समिति प्रबंधक के खिलाफ23 लाख 25 हजार 901 रुपए की वसूली निकाली गई है। थाना बदेरा में दोनों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और 316(5) के तहत एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम धारा 3 और 7 के तहत अपराध दर्ज कराया गया है।

चित्रकूट के पंच प्रयाग घाट पर शराब पीते 7 युवक गिरफ्तार, बोलेरो जीप और अंग्रेजी शराब जब्त

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। धर्मनगरी चित्रकूट में शराब के सार्वजनिक सेवन को लेकर पुलिस की सख्ती का उदाहरण सामने आया है। पंच प्रयाग घाट सती अनुसुइया में कुछ व्यक्तियों द्वारा खुलेआम शराब पीने की सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर रेड की कार्रवाई की, जिसमें सात युवक शराब के नशे में पाए गए। आरोपियों की स्थिति इतनी नशे की थी कि उनके बोलने में अस्पष्टता थी और सांसों से शराब की तीव्र गंध आ रही थी पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ की, जिनमें अजय द्विवेदी (28 वर्ष), दीपू पांडेय (28 वर्ष), अमन पांडेय (16 वर्ष), सौरभ द्विवेदी (23 वर्ष), सुभम द्विवेदी (24 वर्ष), संजय कुमार तिवारी (32 वर्ष) और सूरज उर्फ कृष्णकांत मिश्रा (16 वर्ष) शामिल हैं सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के सकरौली थाना पहाड़ी के निवासी हैं मौके से पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से एक खुली बोतल सिग्नेचर अंग्रेजी शराब (750 एमएल कीमत 940 रुपये), एक आधी बोतल सिग्नेचर (375 एमएल, कीमत 480 रुपये), एक अधभरी किंगफिशर बियर (650 एमएल, कीमत 250 रुपये), आठ डिस्पोजल गिलास (कीमत 20 रुपये) आठ सिगरेट, मूवमेंट कंपनी एक डिब्बी (50 रुपये) दो अधजली सिगरेट और एक प्लास्टिक की 2 लीटर की बोतल जिसमें लगभग एक लीटर पानी था जब्त किया इसके अलावा पुलिस ने मौके से बोलेरो जीप (क्रमांक P96C5216) को भी जब्त किया कार्रवाई के दौरान बोलेरो चालक अजय द्विवेदी द्वारा वाहन के वैध दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस पेश नहीं किए गए, जिससे उसे धारा 130/177(1) व 130/177(3) एम.व्ही. एक्ट के तहत उल्लंघनकारी पाया गया। इसके अतिरिक्त सभी आरोपियों द्वारा सार्वजनिक स्थान पर मदिरापान कर धारा 36(बी) आबकारी एक्ट का उल्लंघन किया गया चूंकि सभी आरोपियों का अपराध जमानती और सात वर्ष से कम की सजा का है इसलिए मौके पर ही धारा 35(3) बी.एन.एस.एस. की नोटिस जारी कर उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने हेतु बाध्य किया गया पुलिस ने थाने वापसी पर अपराध दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है स्थानीय नागरिक इस बात पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं कि पुलिस शराब पीने वालों को तो पकड़ रही है लेकिन प्रतिबंध के बावजूद दबंगाई से बेचने वालों पर नियंत्रण नहीं कर पा रही वहीं प्रशासन इस कार्रवाई को कानून-व्यवस्था के पालन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है।

जनगणना कार्यों की प्रगति की समीक्षा, अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश

मीडिया ऑडीटर, सतना (निप्र)। जनगणना कार्यों की समीक्षा बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में अपर कलेक्टर एवं जिला जनगणना अधिकारी शैलेंद्र सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जनगणना से संबंधित विभिन्न गतिविधियों एवं प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि जनगणना कार्य निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण किए जाएं। इस मौके पर भोपाल के उमेशचन्द्र कुशवाहा और जिला मास्टर ट्रेनर अनुराग वर्धन पाण्डेय द्वारा जनगणना 2027 के पूर्ण कवरेज एवं डाटा की गुणवत्ता को बनाये रखने प्रथम चरण में ग्राम रजिस्टर, नगर रजिस्टर, चार्ज रजिस्टर तैयार करने के निर्देश दिये। जनगणना 2027 के प्रथम चरण मकान सूची एवं मकानों की गणना कार्य में सभी तहसील एवं नगर परिषद के चार्ज अधिकारी और सहयोगी तकनीकी सहायक उपस्थित थे। इस मौके पर नगर जनगणना अधिकारी सत्यम मिश्रा, जनगणना प्रभारी डिप्टी कलेक्टर संदीप परस्ते, जिला कार्यालय के वीरेन्द्र सिंह, कामता चतुर्वेदी, अनुराग सिंह, अखिल सिंह, रितिक वर्मन भी उपस्थित रहे।

स्वत्वाधिकारी मुद्रक प्रकाशक संदीप द्विवेदी द्वारा मीडिया प्रकाशन रीवा से मुद्रित कर मीडिया ऑडीटर कार्यालय प्रभात बिहार कॉलोनी सतना से प्रकाशित, संपादक संदीप द्विवेदी आर.एन.आई नं.एमपीएचआईएन/2021/81683
प्रधान कार्यालय रीवा (सिटी कार्यालय चक्रधर सिटी सेंटर रीवा) फोन. नं. 9407132714, 7974467831 Mediaauditor1@gmail.com पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार, सभी विवादो का न्याय क्षेत्र रीवा होगा।